वर्ष 12 • अंक 308 • 16 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 13 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

आभूषण निर्यात में भारी गिरावट

श्रीनाथ नरसिम्हन ▸▸ पृष्ठ 2

टाटा ट्रस्ट्स के नए सीईओ होंगे श्रीनाथ

डॉलर रु. 71.30 (अपरिवर्तित) | यूरो रु. 77.90 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 40421 ▼ 40 रुपये | सेंसेक्स 41565.90 ▲ 349.80 | निफ्टी 12201.20 ▲ 93.30 | निफ्टी फ्यूचर्स 12228.50 ▲ 27.30 | ब्रेंट क्रूड 55.20 डॉलर ▲ 01.20 डॉलर

एक नज़र

रसोई गैस के दाम प्रति सिलिंडर 144.50 रुपये बढ़े

रसोई गैस की कीमतों में बुधवार को 144.5 रुपये प्रति सिलिंडर की भारी-भरकम वृद्धि की गई। सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी। हालांकि सरकार ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर दी है। इससे सब्सिडी वाले सिलिंडर के उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। कंपनियों ने कहा कि एलपीजी सिलिंडर की कीमत 714 रुपये से बढ़ाकर 858.50 रुपये कर दी गई है। यह जनवरी 2014 के बाद से रसोई गैस के भाव में हुई सबसे बड़ी वृद्धि है। सरकार ने इसके साथ ही एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 153.86 रुपये से बढ़ाकर 291.48 रुपये प्रति सिलिंडर कर दी है।

रेलवे स्टेशनों पर हवाईअड्डों की तरह यूजर चार्ज

रेल से सफर करने वाले यात्रियों को नए सिरे से विकसित स्टेशनों पर हवाईअड्डों की तरह यूजर चार्ज देना होगा जिससे किराये में बढ़ोतरी होगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी के यादव ने बुधवार को बताया कि यूजर डेवलपमेंट फीस उन करों का हिस्सा है जो हवाई यात्रियों को देने पड़ते हैं। यह फीस विभिन्न हवाई अड्डों पर वसूली जाती है और इसकी दर अलग-अलग होती है। नए सिरे से विकसित रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के हिसाब से फीस वसूली जाएगी। रेल मंत्रालय जल्दी ही इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। रेलवे ने अमृतसर, नागपुर, ग्वालियर और साबरमती स्टेशनों के नए सिरे से विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

15 दिन के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा फास्टैग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 29 फरवरी तक फास्टैग पर कोई फीस नहीं लेने का फैसला किया है। सरकार ने देश के 527 राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग आधारित टोल संग्रह व्यवस्था शुरू की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 15 फरवरी से 29 फरवरी तक फास्टैग पर 100 रुपये की फीस माफ करने का फैसला किया गया है। वाहन के वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ किसी भी अधिकृत पॉइंट ऑफ सेल लोकेशन से मुफ्त में फास्टैग लिया जा सकता है।

महाराष्ट्र में कर्मचारी करेंगे हफ्ते में पांच दिन काम

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 29 फरवरी से हफ्ते में पांच कार्यदिवस की घोषणा की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य में सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और स्थानीय निकायों में 20 लाख से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी हैं।

सेंसेक्स 350 अंक चढ़ा, निफ्टी 12,200 अंक के पार

शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी का सिलसिला कायम रहा। वैश्विक बाजारों में लाभ के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में तेजी के बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 349.76 अंक बढ़त के साथ 41,565.90 पर बंद हुआ। निफ्टी 93.30 अंक चढ़कर 12,201.20 पर बंद हुआ।

व्यापार गोष्ठी

आयकर की दोहरी प्रणाली कितनी सुगम?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या विवाद से विश्वास योजना के विस्तार से बढ़ेगा सरकार का राजस्व

www.bshindi.com **पर राय भेजें।** आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या विदेश पैसे भेजने पर टीसीएस काटने का निर्णय सही है? हां **64.71%** नहीं **35.29%**

विवाद से विश्वास योजना का दायरा बढ़ाया

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 12 फरवरी

- विवाद से विश्वास योजना का दायरा बढ़ाने को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- सीतारमण ने पिछले सप्ताह लोक सभा में पेश किया था विधेयक
- ऋण वसूली पंचाटों में लंबित मामले होंगे शामिल
- कर संशोधन और तलाशी तथा जब्ती के छोटे मामलों को भी जगह

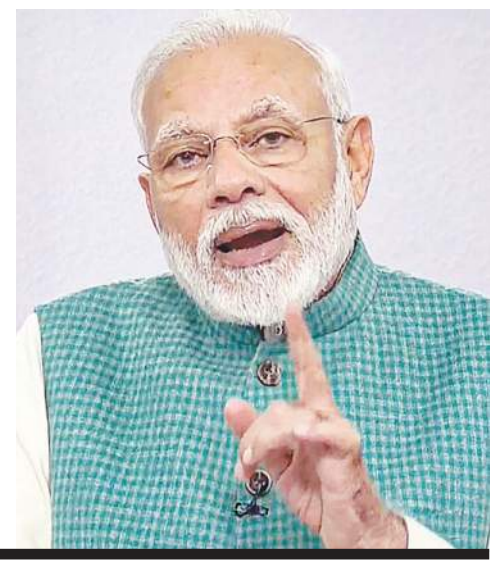

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना को आकर्षक बनाने के लिए इसमें बदलाव को आज मंजूरी दे दी। इस बदलाव का मकसद इसका दायरा बढ़ाकर मध्यस्थता और ऋण वसूली पंचाटों में लंबित मुकदमों को भी इसमें शामिल करना है। इसके अलावा कर संशोधन और तलाशी तथा जब्ती के छोटे मामले भी इसमें शामिल किए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9.3 लाख करोड़ रुपये से संबंधित विवादित कर मामलों के समाधान के लिए एक सप्ताह पहले प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 लोक सभा में पेश किया था। उन्होंने अपने बजट भाषण में यह विधेयक लाने की घोषणा की थी।

इस योजना के तहत कर विवाद से जुड़े मामले के निपटारे के लिए ब्याज, जुर्माना और सजा माफ करने का प्रावधान है। पहले यह योजना 31 जनवरी, 2020 तक आयुक्त (अपील), आय कर अपील पंचाट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों तक ही सीमित थी लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। इसके तहत 31 मार्च तक विवाद का निपटारा करने पर ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा जबकि इसके बाद विवादित राशि का 10 फीसदी अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऋण वसूली पंचाटों, मध्यस्थता पंचाटों और अदालतों में लंबित मुकदमों और कर संशोधन से जुड़े सभी मामलों को इस योजना में शामिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पक्षों की तरफ से मिले सुझावों के आधार पर यह फैसला किया गया है। जावडेकर ने कहा, 'आम बजट के बाद वित्त मंत्री ने विभिन्न पक्षों से चर्चा करके इस बारे में सुझाव मांगे थे। इन सुझावों के आधार पर संसद के इस सत्र में नए संशोधन किए जा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि तलाशी और जब्ती से जुड़े ऐसे मामले भी इस योजना में शामिल किए जाएंगे जहां वसूल की गई राशि 5 करोड़ रुपये से कम है। जावडेकर ने कहा कि इस कवायद का मकसद विधेयक के दायरे को बढ़ाना है।

अशोक माहेश्वरी ऐंड एसोसिएट्स एलएलपी में मैनेजिंग पार्टनर अमित माहेश्वरी ने विधेयक में संशोधन के फैसले को सही कदम बताते हुए कहा कि इससे करदाताओं को अपने मामले निपटाने में आसानी होगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना का मकसद राजस्व जुटाना और मुकदमों की संख्या में कमी लाना है तो फिर विभिन्न पंचाटों के तहत लंबित मामलों को इस योजना से बाहर रखने का कोई मतलब नहीं है। तलाशी और जब्ती के छोटे मामलों को भी इस योजना में शामिल करना अच्छा कदम है और इससे खासकर ऐसे करदाताओं को मदद मिलेगी जिनका मामला कमजोर है। इससे फंसा हुआ कर राजस्व विवादमुक्त होगा और लंबित मामलों की संख्या घटाने में मदद मिलेगी। तलाशी के कई मामले मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं और अब उन्हें भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। यह योजना 30 जून तक जारी रहेगी। अगर कर बकाया केवल विवादित ब्याज या और जुर्माने से जुड़ा है तो 31 मार्च तक विवाद का निपटारा करने पर विवादित जुर्माने/ब्याज की 25 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा, उसके बाद यह राशि 30 फीसदी हो जाएगी।

एएमआरजी एसोसिएट्स के रजत मोहन ने कहा कि अप्रत्यक्ष कर के लिए विवाद समाधान योजना की नाकामी के बाद सरकार विवाद से विश्वास योजना को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह योजना सभी मामलों पर लागू होगी, चाहे उनके कर मांग लंबित हो या इसका भुगतान कर दिया गया हो। हालांकि, ऐसा लगता है कि अघोषित विदेशी आय या संपत्ति और दोहरे कराधान से बचने के लिए किए गए समझौते के तहत मिली जानकारी के आधार पर किए गए कर आकलन और पुनर्आकलन के मामलों को अब भी योजना से बाहर रखा गया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड बेस्ट बी-स्कूल अवॉर्ड

फोटो: कमलेश पेडणेकर

बिज़नेस स्टैंडर्ड बेस्ट बी-स्कूल प्रोजेक्ट अवॉर्ड 2019 के प्रथम उपविजेता जी तेजा, विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी खड़गपुर, विजेता कपिल गवली, एनआईटीआईई, मुंबई और दूसरे उपविजेता आयुष त्रिवेदी, एससीएमएचआरडी, पुणे तथा विवेक सत्यमूर्ति, एक्सआईएमई, चेन्नई (बाएं से)। (संबंधित खबर पृष्ठ 16)

वॉकहार्ट ने बेचा ब्रांडेड कारोबार में अपना हिस्सा

वित्तीय संकट से जूझ रही दवा कंपनी वॉकहार्ट ने भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव में अपनी ब्रांडेड जेनरिक दवा कारोबार का एक हिस्सा डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) को बेच दिया है। कंपनी ने हिमाचल प्रदेश में एक विनिर्माण संयंत्र का सौदा भी डीआरएल के साथ किया है। यह सौदा 1,850 करोड़ रुपये में हुआ है। वॉकहार्ट को उम्मीद है कि इस सौदे से उसे एंटीबॉयोटिक उत्पाद कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने और इसमें नकदी झोकने में मदद मिलेगी। वॉकहार्ट के बोर्ड ने बुधवार को बिक्री प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस सौदे के मई 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। ब्रांडेड जेनरिक दवा कारोबार स्लंप सेल बेसिस पर किया गया है। इस सौदे के तहत 62 दवा ब्रांड का एक पोर्टफोलियो डीआरएल को स्थानांतरित किया जाएगा। पृष्ठ 2

खुदरा महंगाई बढ़ी और औद्योगिक उत्पादन घटा

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 12 फरवरी

- जनवरी में खुदरा महंगाई पांच साल के उच्च स्तर 7.59 फीसदी पर पहुंची
- दिसंबर में आईआईपी 0.3 फीसदी घटा
- अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत के लिए अभी करना होगा इंतजार

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में थोड़ा सुधार होने को देखते हुए संभवत: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत बताए थे लेकिन यह तेजी अस्थायी थी क्योंकि दिसंबर में फिर से औद्योगिक उत्पादन 0.3 फीसदी घट गया।

दूसरी ओर खाद्य पदार्थों की कीमतों में थोड़ी नरमी आने के बाद भी खुदरा महंगाई जनवरी में 56 माह के उच्च स्तर 7.59 फीसदी पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में 7.35 फीसदी रही थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर में गिरावट मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि की वजह से आई है। बिजली क्षेत्र में भी गिरावट का रुख बना हुआ है। दिसंबर में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर में 1.2 फीसदी की गिरावट आई जबकि नवंबर में 2.7 फीसदी बढ़त दर्ज की गई थी। बिजली क्षेत्र का उत्पादन दिसंबर में 0.1 फीसदी घटा। आईआईपी में केवल खनन क्षेत्र में ही सुधार देखा गया, जिसकी वृद्धि दर 5.4 फीसदी रही जबकि नवंबर में इसमें 1.7 फीसदी का इजाफा हुआ था।

नवंबर से पहले आईआईपी में लगातार तीन महीने गिरावट आई थी। ऐसे में नवंबर के आंकड़ों में सुधार के संकेत दिखे थे।

पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में भी दिसंबर में नरमी देखी गई। इसका उत्पादन 18 फीसदी घटा जबकि नवंबर में इसमें 8.6 फीसदी की गिरावट आई थी। इसका असर आने वाले महीनों में भी औद्योगिक उत्पादन पर पड़ सकता है।

केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि आईआईपी में गिरावट क्षमता की कम उपयोगिता के कारण कम निवेश का संकेत है। उपभोक्ता वस्तुओं के साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का उत्पादन भी दिसंबर में घटा है। सबनवीस ने कहा कि यह मांग में कमी को दर्शाता है।

इंडिया रेटिंग्स में प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि औद्योगिक उत्पादन में सुधार नहीं दिख रहा है और इसमें सुधार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

दूरसंचार फर्मों से एजीआर वसूली की तैयारी में विभाग

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 12 फरवरी

- कंपनियों की याचिका पर इस सप्ताह सुनवाई शुरू नहीं हुई तो दूरसंचार विभाग भेजेगा वसूली के लिए पत्र
- विभाग ने पहले वसूली में सख्ती नहीं बरतने के दिए थे संकेत

दूरसंचार विभाग भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया वसूलने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर उच्चतम न्यायालय इस सप्ताह इन कंपनियों की याचिका पर सुनवाई नहीं करता है तो विभाग उन्हें एजीआर बकाये की वसूली के लिए पत्र भेज सकता है।

विभाग के अधिकारियों का मानना है कि दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाये का भुगतान करना शुरू कर देना चाहिए था।

एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, विभाग ने कहा था कि वह 23 जनवरी की समयसीमा के समाप्त होने तक वसूली के लिए कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय भी कंपनियों की संशोधित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। लेकिन कंपनियां हमारे आदेश की ऐसी व्याख्या नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है।' उन्होंने कहा कि कंपनियों को उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश के मुताबिक भुगतान करना शुरू कर देना चाहिए था। अधिकारी ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय इस सप्ताह कंपनियों की संशोधित याचिका पर सुनवाई नहीं करता है तो दूरसंचार विभाग उन्हें भुगतान के लिए पत्र जारी करना शुरू कर देगा।

उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर के आदेश के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को 24 जनवरी तक 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना था। यह राशि 15 दूरसंचार कंपनियों पर बकाया है। हालांकि उनमें से कई कंपनियां अब अपना कारोबार बेच चुकी हैं या समेट चुकी हैं।

दूरसंचार विभाग ने 23 जनवरी को कंपनियों को अंतरिम राहत देते हुए अगर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक एजीआर बकाये का भुगतान करने में नाकाम रहती हैं, तो उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। विभाग के लाइसेंसिंग फाइनैंस पॉलिसी विंग (एलएफपीडब्ल्यू) ने 23 जनवरी को विभिन्न सर्किलों के संचार लेखा नियंत्रकों को जारी एक परिपत्र में कहा कि किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। कंपनियों को पहले ही बताया जा चुका है कि उन्हें दूरसंचार विभाग के मुख्यालय को भुगतान करना है।

केजरीवाल 16 फरवरी को लेंगे शपथ

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को यहां के रामलीला मैदान में भव्य समारोह में लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि कार्यक्रम में केजरीवाल के साथ सभी मंत्री भी शपथ लेंगे। आप के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी रविवार को विशाल कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को आमंत्रित करने की योजना बना रही है और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। शपथ ग्रहण समारोह के स्थल के तौर पर रामलीला मैदान को चुने जाने का काफी महत्त्व है क्योंकि यही वह मैदान था जहां से अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने विशाल भ्रष्टाचार रोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था जो आखिरकार उनके राजनीतिक करियर के आगाज का शुरुआती मंच बना। *भाषा*

आईटी में रहेगा उत्पाद केंद्रित वृद्धि पर जोर

देवाशीष महापात्र
बेंगलूरु, 12 फरवरी

नैसकॉम टेक्नोलॉजी ऐंड लीडरशिप फोरम 2020 में शिरकत करते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी एवं सीईओ राजेश गोपीनाथन, इन्फोसिस के एमडी एवं सीईओ सलिल पारेख और विप्रो के कार्यकारी चेयरमैन रिशद प्रेमजी (बाएं से दाएं)। *फोटो : पीटीआई*

ऐसा विरले ही होता है जब देश की तीन शीर्ष आईटी फर्मों के प्रमुख एकसाथ एक मंच पर नजर आएं। तीनों प्रतिस्पर्द्धी कंपनियों के दिग्गज नैसकॉम के प्रमुख आईटी कार्यक्रम में नजर आए और उद्योग की स्थिति और आगे के परिदृश्य पर चर्चा की।

नैसकॉम द्वारा आयोजित सालाना आईटी कार्यक्रम से इतर बातचीत के एक सत्र में टाटा कंसल्टेंसी के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन, इन्फोसिस के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक सलिल पारेख और विप्रो के कार्यकारी चेयरमैन रिशद प्रेमजी ने इस पर सहमति जताई कि निर्यात आधारित आईटी उद्योग के लिए समय चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। ऐसे में इस क्षेत्र की घरेलू कंपनियां उत्पाद आधारित वृद्धि की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

12 लाख करोड़ रुपये से अधिक समेकित बाजार पूंजी और करीब 6 लाख कर्मचारियों वाली इन तीनों कंपनियों के प्रमुखों ने उद्योग की स्थिति को लेकर भी समान विचार साझा किए। रिशद प्रेमजी, जो नैसकॉम के चेयरमैन रह चुके हैं, ने कहा, 'हमारा सिद्धांत उत्पाद और सेवाओं का एकीकरण तथा उन्हें अपने ग्राहकों को आपूर्ति करना है। हम सेवाओं को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं।'

टीसीएस के गोपीनाथन ने कहा, 'अगर आप वैश्विक स्तर पर तीन शीर्ष बैंकिंग प्लेटफॉर्म को देखें तो इसमें भारतीय आईटी सेवा प्रदाताओं का अहम योगदान है।' इसी तरह इन्फोसिस के पारेख ने कहा कि आने वाले वर्षों में उत्पाद आधारित कारोबार के विकास के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। टीसीएस का बैंक्स और इन्फोसिस का फिनेकल दो सर्वाधिक चर्चित बैंकिंग प्लेटफॉर्म हैं, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के प्रमुख बैंकों द्वारा किया जाता है।

भारतीय आईटी फर्में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए धीरे-धीरे अपना उत्पाद और प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं। इससे आईटी फर्में न केवल बेहतर मूल्य निर्धारण की स्थिति में होंगे बल्कि भविष्य में इन परिसंपत्तियों से मुद्रीकरण के अवसर भी मिल सकते हैं।

तीनों आईटी दिग्गजों ने कहा कि यह रणनीति भले ही निकट भविष्य में पारंपरिक राजस्व पर थोड़ा प्रभाव डाले लेकिन निवेशकों के लिए यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।

खबरों में रहे स्टॉक

सिएट

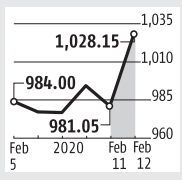

चेन्नई में कंपनी के नए संयंत्र का उदघाटन

₹ 981.05 पिछला बंद भाव
₹ 1,028.15 आज का बंद भाव
▲ 4.80 %

आईडीबीआई बैंक

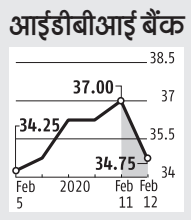

तीसरी तिमाही में नुकसान बढ़कर 5,763 करोड़ रुपये पर पहुंचा

₹ 37.00 पिछला बंद भाव
₹ 34.75 आज का बंद भाव
▼ 6.08 %

एचईजी

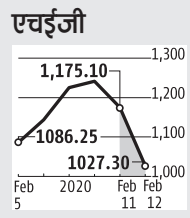

तीसरी तिमाही में 1 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान

₹ 1,175.10 पिछला बंद भाव
₹ 1,027.30 आज का बंद भाव
▼ 12.58 %

इप्का लैबोरेटरीज

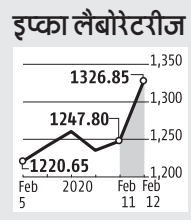

तीसरी तिमाही में एकीकृत एबिटा मार्जिन 23.56 फीसदी रहा

₹ 1,247.80 पिछला बंद भाव
₹ 1,326.85 आज का बंद भाव
▲ 6.34 %

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स

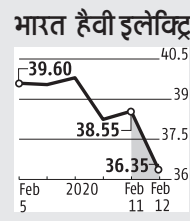

तीसरी तिमाही में परिचालन राजस्व 23.3 फीसदी घटा

₹ 38.55 पिछला बंद भाव
₹ 36.35 आज का बंद भाव
▼ 5.71 %

संक्षेप में

आईटी क्षेत्र की आय 7.7 प्रतिशत बढ़ेगी: नैसकॉम

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का संगठन नैसकॉम ने चालू वित्त वर्ष में क्षेत्र की कंपनियों की आय 7.7 प्रतिशत बढ़कर 191 अरब डॉलर रहने का अनुमान जताया है। उद्योग संगठन पिछले दो दशक से आईटी क्षेत्र में आय वृद्धि का अनुमान देता आ रहा है। लेकिन उसने पिछले वित्त वर्ष में आय वृद्धि का अनुमान नहीं दिया था। इस बारे में उसका कहना था कि उद्योग में चीजें तेजी से बदल रही हैं और इसलिए उसने 2019-20 में आय वृद्धि के बारे में अनुमान नहीं दिया था। सालाना नैसकॉम लीडरशिप कार्यक्रम में संगठन के चेयरमैन केशव मुरूगेश ने कहा कि सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की आय 7.7 प्रतिशत बढ़कर 191 अरब डॉलर रहेगी। *भाषा*

रिलायंस के वरिष्ठ सलाहकार बने बेहुरिया

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओसी) के पूर्व चेयरमैन सार्थक बेहुरिया को रिलायंस इंडस्ट्रीज का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह कंपनी के खुदरा कारोबार को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे। 68 वर्षीय, बेहुरिया पिछले साल तक अदाणी समूह के साथ थे। सूत्रों ने बताया कि बेहुरिया रिलायंस के ब्रिटेन की बीपी के साथ नए ईंधन के खुदरा संयुक्त उद्यम को रणनीतिक दिशा और नेतृत्व देने का काम करेंगे। बीपी पीएलसी ने पिछले साल रिलायंस के ईंधन खुदरा कारोबार में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 7,000 करोड़ रुपये में किया था। *भाषा*

एनसीडीईएक्स ने सेबी को सौंपे दस्तावेज

नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ने आईपीओ लाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के समक्ष पेशकश का दस्तावेज जमा किया है। दस्तावेज के अनुसार, आईपीओ में 100 करोड़ रुपये तक के नए निर्गम और शेयरधारकों के 1,44,53,774 शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल होगी। मर्चेंट बैंकिंग के सूत्रों ने बताया कि इस आईपीओ से 500 करोड़ रुपये की पूंजी जुटने का अनुमान है। जो शेयरधारक शेयरों की बिक्री की पेशकश करेंगे, उनमें बिल्ड इंडिया कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी, केनरा बैंक, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड, इंवेस्टकॉर्प प्राइवेट इक्विटी फंड-1, जेपी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, नैशनल बैंक फोर एग्रीकल्चर ऐंड रूरल डेवलपमेंट, और पीएनबी आदि शामिल हैं। *भाषा*

वॉकहार्ट ने बेचे कुछ कारोबार

कंपनी ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ 1,850 करोड़ रुपये में किया सौदा

सोहिनी दास और बी दशरथ रेड्डी
मुंबई/हैदराबाद, 12 फरवरी

कर्ज बोझ से दबी दवा कंपनी वॉकहार्ट ने बुधवार को भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव में अपनी ब्रांडेड जेनरिक दवा कारोबार का एक हिस्सा खंड डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) को बेच दिया। कंपनी ने एक विनिर्माण संयंत्र का सौदा भी डीआरएल के साथ किया है। यह सौदा 1,850 करोड़ रुपये में हुआ है। कंपनी के जेनरिक दवा कारोबार का मूल्यांकन सालाना राजस्व के 3.8 गुना स्तर पर किया गया है। वॉकहार्ट को उम्मीद है कि इस सौदे से उसे एंटीबायोटिक उत्पाद खंड पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मौजूदा कारोबारों में नकदी डालने में मदद मिलेगी। वॉकहार्ट के निदेशक मंडल ने बुधवार को बिक्री प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और माना जा रहा है कि यह सौदा मई 2020 तक पूरा हो जाएगा। ब्रांडेड जेनरिक दवा कारोबार स्लंप सेल बेसिस (एकमुश्त रकम के लिए एक से अधिक कारोबार की बिक्री) पर किया गया है।

इस सौदे के तहत विभिन्न खंडों जैसे श्वास, स्नायु तंत्र, वीएमएस, चर्मरोग चिकित्सा, पेट, दर्द एवं टीका आदि खंडों के 62 दवा ब्रांड का एक पोर्टफोलियो डीआरएल को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ वॉकहार्ट ने कारोबारी परिसंपत्तियां एवं देनदारी, अनुबंध, अनुमति, बौद्धिक संपदा, कर्मचारी, विपणन एवं बिक्री और इस पोर्टफोलियो का वितरण (भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में) भी डीआरएल को सौंप दिया है। कंपनी हिमाचल प्रदेश के बद्दी में अपना संयंत्र भी डीआरएल को बेच रही है और इस संयंत्र के सभी कर्मचारी भी डीआरएल के तहत काम करेंगे।

वित्त वर्ष 2019 में इस कारोबार खंड ने कंपनी के कुल एकीकृत राजस्व का 28 प्रतिशत (594 करोड़ रुपये) का अंशदान दिया। समेकित राजस्व में भी इसकी हिस्सेदारी 14 प्रतिशत रही। 31 दिसंबर को समाप्त हुई नौ महीने की अवधि में इस कारोबार ने 34 प्रतिशत (एकीकृत राजस्व का) योगदान दिया।

वॉकहार्ट के संस्थापक चेयरमैन एवं समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हबील खोराकीवाली ने कहा, 'कंपनी गंभीर चिकित्सा खंडों से निकलकर अब पुरानी बीमारियों-मधुमेह, केंद्रीय स्नायु तंत्र (सीएनएस)- के इलाज में काम आने वाली दवाओं के कारोबार की तरफ बढ़ना चाहती है। इस कारोबारी खंड की बिक्री के पीछे कंपनी की यही रणनीति है।' खोराकीवाला ने कहा कि ब्रांडेड जेनरिक दवा पोर्टफोलियो की बिक्री से कारोबार में नकदी डालने और एंटीबायोटिक कारोबार पर ध्यान देने में मिलेगी मदद पर्याप्त नकदी भी मिलेगी, जिसका इस्तेमाल पुरानी बीमारियों के इलाज की दवाओं के कारोबार, अंतरराष्ट्रीय परिचालन, अमेरिकी बाजार में बायोसिमिलर में निवेश के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कंपनी शोध एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी इस नकदी का इस्तेमाल करेगी। वॉकहार्ट यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, आयरलैंड और कुछ दूसरे देशों में अपने कारोबार पर अपनी सहायक इकाइयों के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण जारी रखेगी। दूसरी तरफ डीआरएल अधिग्रहण को अपने घरेलू कारोबार को मजबूती देने का एक जरिया मान रही है।

डीआरएल के को-चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जी वी प्रसाद ने कहा,' भारत हमारे लिए एक महत्त्वपूर्ण बाजार है। इस अधिग्रहण से हमें घरेलू कारोबार को गति देने में खासी मदद मिलेगी। अधिग्रहण से अधिक मुनाफा देने वाले कारोबार में डीआरएल की उपस्थिति बढ़ेगी। हमार मानना है कि वॉकहाड्र्ट से हासिल हो रहे पोर्टफोलियो से काफी संभावनाएं जुड़ी हैं और डीआरएल के तहत इनमें और इजाफा होगा।'

डीआरएल ने इससे पहले 2015 में भारत केंद्रित उत्पाद का अधिग्रहण किया था। बुधवार को वॉकहाड्र्ट का शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर 6.68 प्रतिशत गिरावट के साथ 367.15 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी तरफ, डीआरएल का शेयर मामूली चढ़कर 3,197.55 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

रणनीति का हिस्सा!

- वॉकहार्ट ने भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव में ब्रांडेट जेनरिक कारोबार का एक हिस्सा डीआरएल को बेचा
- 1,850 करोड़ रुपये के सौदे में 62 उत्पादन और बद्दी संयंत्र शामिल
- सौदे से वॉकहार्ट को अपने
- वॉकहार्ट पर दिसंबर तक 2,300 करोड़ रुपये कर्ज
- डीआरएल को सौदे से भारत में उपस्थिति मजबूत होने की उम्मीद

टाटा ट्रस्ट्स के नए सीईओ होंगे श्रीनाथ

देव चटर्जी
मुंबई, 12 फरवरी

टाटा ट्रस्ट्स के न्यासी ने टाटा समूह के श्रीनाथ नरसिम्हन को ट्रस्ट्स का मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। नरसिम्हन ऐसे समय में ट्रस्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं जब इसका (ट्रस्ट्स का) आयकर विभाग के साथ विवाद चल रहा है और टाटा समूह पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और समूह के संरक्षक रतन टाटा की आपसी लड़ाई में फंसी है।

टाटा संस में ट्रस्ट्स की 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। टाटा संस टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है और लाभांश आय का इस्तेमाल परोपकार के कार्यक्रम संचालित करने के लिए करती है। नरसिम्हन फिलहाल टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। नरसिम्हन टाटा समूह में कई जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। वह1986 में टाटा प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े थे।

न्यासियों ने सिटी इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी प्रमित झवेरी को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का न्यासी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति बुधवार से प्रभावी हो गई है। पिछले वर्ष फरवरी में आर वेंकटरमणन ने टाटा ट्रस्ट्स के प्रबंध न्यासी (मैनेजिंग ट्रस्टी) के पद से इस्तीफा दे दिया था। नए सीईओ को मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि वेंकटरमणन का ऊंचा वेतन चर्चा का विषय बन गया था। आयकर विभाग ने वेंकटरमणन के सालाना 2.66 करोड़ रुपये वेतन की जांच-पड़ताल की थी और उसके बाद सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को दी कर रियायत वापस ले ली थी। बाद में एक समिति ने सीईओ का चयन करने के लिए कई आंतरिक कर्मचारियों एवं दूसरी जगहों के पेशेवरों का साक्षात्कार लिया था। अंतत: समिति ने सीईओ के लिए नरसिम्हन का चयन किया।

वेंकटरमणन के इस्तीफे के बाद टाटा ट्रस्ट का परिचालन का प्रबंधन टाटा समूह कुछ प्रमुख कर्मचारियों के कर रही थी। संगठन में हाल में किए गए बदलावों के रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को श्री रतन टाटा ट्रस्ट का न्यासी बनाया गया है। नरसिम्हन के सामने तत्काल सबसे बड़ी चुनौती आकयर विभाग के साथ चल रहे विवाद से निपटने की होगी।

तेल-गैस क्षेत्र में सिविल वर्क में उतरेगी केआईसी इंटरनैशनल

अमृता पिल्लई
मुंबई, 12 फरवरी

केंद्र सरकार द्वारा गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दिए जाने के कारण इंजीनियरिंग कंपनी केईसी इंटरनैशनल भारत के तेल एवं गैस खंड में सिविल वर्क के अवसरों में हाथ आजमाने पर विचार कर रही है। इंजीनियरिंग क्षेत्र की प्रमुख प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा अपनी ही आर्थिक लड़ाई में व्यस्त होने की वजह से केआईसी इस बाजार में प्रवेश के लिए इसे सही मौके के रूप में देख रही है। केईसी इंटरनैशनल के मुख्य कार्याधिकारी और प्रबंध निदेशक विमल केजरीवाल ने कहा कि हम तेल और गैस क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं जिसमें टैंकेज, संबंधित बुनियादी ढांचा (तेल और गैस परियोजनाओं के लिए) तथा उत्पाद और कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइनों जैसी परियोजनाएं शामिल रहेंगी।

- सिविल ऑर्डरों के लिए तेल और गैस खंड तक पहुंच बनाने पर ध्यान
- पाइपलाइनों, टैंकेज और सहायक परियोजना कार्यों पर लगाएगी बोली
- वित्त वर्ष 20 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां करेंगी 93,639 करोड़ रुपये का व्यय
- भारत में गैस आधारित बुनियादी ढांचे पर किया जाना है 60 अरब डॉलर का निवेश

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय, पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

घरेलू कंपनियों की नजर रक्षा उद्योग पर

आदिति दिवेकर
मुंबई, 12 फरवरी

अगले वित्त वर्ष में रक्षा बजट में 6 प्रतिशत मामूली बढ़ोतरी के बावजूद जिंदल डिफेंस और एलऐंडटी डिफेंस रक्षा उद्योग में भाग लेने में सक्रियता दिखा रही हैं। इस समय भारत ज्यादातर रक्षा उपकरणों का आयात करता है।

हाल में ही लार्सन ऐंड टुब्रो (एलऐंडटी) और मिसाइल प्रणाली में दुनिया की अग्रणी कंपनी यूरोप स्थित एमबीडीए ने तमिलनाडु में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की है। ओ पी जिंदल ग्रुप की कंपनी जिंदल डिफेंस ने भी भारत में छोटे हथियार विनिर्माण में कदम रखने की बात कही है। कंपनी ने ब्राजील की टॉरस अरमास के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है।

इस बारे में जिंदल डिफेंस के प्रवर्तक अभ्युदय जिंदल ने कहा, 'इस समय विदेशी कंपनियां भारत के रक्षा उपकरणों की कुल जरूरतों का 50 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2035 तक भारत में छोटे हथियारों का बाजार 10 से 12 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। इससे घरेलू कंपनियों को रक्षा विनिर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिलता है।'

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन नीति, 2018 के तहत रक्षा उद्योग 26 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 7 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात भी शामिल है। एलऐंडटी (रक्षा कारोबार) में निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष (डिफेंस ऐंड स्मार्ट टेक्नोलॉजिज) जे डी पाटिल ने कहा,'इस वजह से घरेलू उद्योग के लिए संचयी अनुमानित पूंजीगत व्यय करीब 10 लाख करोड़ रुपये होगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बाद रक्षा उद्योग का स्थानीयकरण 35-40 प्रतिशत से बढ़कर 70-75 प्रतिशत तक होना चाहिए। इस लिहाज से घरेलू रक्षा उद्योग कंपनियों के लिए काफी संभावनाएं हैं।'

एलऐंडटी का संयुक्त उद्यम सशस्त्र सेनाओं के लिए पूर्ण मिसाइल प्रणाली तैयार करेगा। इस बीच, रक्षा उद्योग में आई नई कंपनी जिंदल डिफेंस हिसार में अपनी छोटी शस्त्र इकाई के लिए 5 करोड़ डॉलर निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी शुरुआती चरण में निजी निवेश पर ध्यान दे रही है और बाद में वित्तीय रकम जुटाने के अवसर तलाशेगी। जिंदल दीर्घ अवधि में रक्षा उपकरण विनिर्माण उद्योग में एक महत्त्वपूर्ण इकाई बनना चाहती है, जो रक्षा उपकरण आयात में कमी करने में मददगार होगी।

जिंदल ने कहा, 'हमारी मुख्य प्रतिस्पर्द्धा मोटे तौर पर वैश्विक रक्षा उपकरण विनिर्माता कंपनियों से होगी। भारत में इस उद्योग में कई दूसरी निजी कंपनियां भी हैं। हालांकि देश की रक्षा जरूरतों की मांग पूरी करने की उनकी क्षमता फिलहाल काफी कम है। हमारा मुख्य ध्यान आयात पर निर्भरता कम करने पर होगा।' विशेषज्ञों के अनुसार भारत दुनिया के उन पांच शीर्ष देशों में शामिल है, जो रक्षा क्षेत्र पर सर्वाधिक खर्च करता है। देश को रक्षा खंड में आत्मनिर्भर बनने के लिए लंबा सफर तय करना है, लेकिन इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए इसके पास पर्याप्त क्षमताएं मौजूद हैं। रणनीतिक साझेदारी प्रारूप का उद्देश्य रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता कम करना और निजी कंपनियों को रक्षा खरीद में प्रवेश का अवसर मुहैया कराना है।

- रक्षा क्षेत्र मध्यम से दीर्घ अवधि में 'मेक इन इंडिया' में दे सकता है बड़ा योगदान
- 2035 तक देश में छोटे हथियारों का अनुमानित बाजार 12 अरब डॉलर होगा
- घरेलू रक्षा उद्योग में अगले छह वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय का अनुमान
- भारत ज्यादातर रक्षा उपकरणों का विदेश से करता है आयात

इलेक्ट्रिक वाहन की सुस्त रहेगी रफ्तार

पवन लाल
मुंबई, 12 फरवरी

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के तमाम प्रयासों के बावजूद वाहन बाजार में परंपरागत इंजन वाले कारों का ही बोलबाला रहेगा। कम से कम अगले एक दशक तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तस्वीर बदलती नहीं दिख रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के आगे बढ़ने की राह में कई दिक्कतें आ रही हैं, जिनमें देश में चार्जिंग सुविधाओं का अभाव सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है।

आईएचस मार्किट के एक शोध के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं का अभाव, ऊंची कीमतें और दोपहिया एवं व्यावसायिक वाहनों के विद्युतीकरण पर अधिक जोर से ऐसे वाहनों (इलेक्ट्रिक) की बाजार हिस्सेदारी 2030 तक केवल 4 प्रतिशत रह सकती है। देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान यात्री कारों की बिक्री 30 लाख से अधिक रही है। क्रिसिल रिसर्च के एक शोध के अनुसार 2024 तक देश में नए तिपहिया एवं दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक संस्करण की हिस्सेदारी क्रमश: 43-48 प्रतिशत और 12-17 प्रतिशत रहेगी। हालांकि इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों की मांग उतनी नहीं रहेगी। माना जा रहा है कि ऐसे वाहनों की कुल बिक्री में केवल 5 प्रतिशत ही बिजली से चलने वाले वाहन होंगे। टाटा मोटर्स में अध्यक्ष (ई-मोबिलिटी बिजनेस ऐंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी) शैलेश चंद्रा का कहना है कि निजी खंड के लिए फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड ऐंड इलेक्ट्रिक वाहनों की सुविधा देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। चंद्रा ने कहा, 'व्यक्तिगत खंड फ्लीट सेगमेंट के मुकाबले 7 से 8 गुना तक बड़ा है, इसलिए इस खंड (पर्सनल खंड) में थोड़ी बहुत पहुंच बढ़ने से भी इलेक्ट्रिक वाहनों को खासी मिल सकती है।' पहले सरकार ने 2020 तक सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद 15 प्रतिशत करने और 2030 तक इनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह पूरा होता नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचे जैसे चार्जिंग स्टेशन एवं बिजली आउटलेट निजी आवासों एवं ऑफिस पार्क तक ही सीमित रहेंगे। महिंद्रा इलेक्ट्रि के मुख्य कार्याधिकारी महेश बाबू ने कहा, 'चार्जिंग ढांचे की कमी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है।'

आईएचएस मार्किट में प्रिंसिपल एनालिस्ट सूरज घोष के अनुसार इस समय देश में प्रत्येक 100 वाहनों पर एक परंपरागत ईंधन स्टेशन उपलब्ध है। घोष के अनुसार 15 वर्ष पहले आए सीएनजी के मामले में प्रत्येक 2000 वाहनों के लिए एक स्टेशन उपलब्ध है। उन्होंने कहा, 'इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा तुरंत तैयार नहीं होगा और जब तक यह बड़े पैमाने पर तैयार नहीं होगा तब तक लोग इलेक्ट्रिक वाहन लेने से कतराएंगे।' इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल करने के बाद इसकी बिक्री से कितनी रकम मिलेगी यह बात भी एक प्रमुख वजह साबित हो रही है।

म्युचुअल फंडों के लिए निवेश वाली मिडकैप फर्में होंगी दोगुनी

जश कृपलानी
मुंबई, 12 फरवरी

फंडों के लिए बढ़ेगा निवेश का दायरा

- सेबी की अगली बोर्ड बैठक 17 फरवरी को म्युचुअल फंडों के लिए निवेश वाली मिडकैप कंपनियों की संख्या में 150 का इजाफा संभव
- इसके अलावा म्युचुअल फंडों के लिए लार्जकैप कंपनियों की सूची में 25 नाम और जोड़े जा सकते हैं
- मौजूदा ढांचे के मुताबिक, मिडकैप फंडों को अपने कोष का कम से कम 65 फीसदी मिडकैप शेयरों में निवेश करना होता है

बाजार नियामक सेबी म्युचुअल फंडों के लिए निवेश वाली मिडकैप कंपनियों की संख्या में 150 का इजाफा कर सकता है और सेबी की अगली बोर्ड बैठक 17 फरवरी को ऐसा होने की संभावना है। इससे म्युचुअल फंडों के लिए निवेश वाली मिडकैप कंपनियों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिनमें वे अपनी पसंद के मुताबिक निवेश कर पाएंगे।

इसके अलावा म्युचुअल फंडों के लिए लार्जकैप कंपनियों की सूची में 25 नाम और जोड़े जा सकते हैं, जिससे इक्विटी योजनाओं (बड़ी कंपनियों पर केंद्रित) के जरिए निवेश के लिए उनके पास 125 लार्जकैप कंपनियों की सूची होगी

इससे पहले उद्योग ने इस बारे में अपनी राय सेबी के सामने रखी थी। विगत में म्युचुअल फंडों ने शेयर चयन में और लचीला रुख अपनाने के लिए बाजार नियामक से संपर्क किया था।

एक फंड हाउस के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, मिडकैप में ज्यादातर म्युचुअल फंडों का निवेश एक ही तरह के शेयरों में होता है क्योंकि 150 शेयरों की सीमा बनी हुई है। इससे फंड मैनेजरों के लिए उम्दा रिटर्न हासिल करना मुश्किल होता था। सेबी निवेश वाली मिडकैप कंपनियों की संख्या में 100 से 150 कंपनियों का इजाफा कर सकता है।

बेंचमार्क बीएसई 150 मिडकैप और सेबी की तरफ से निवेश वाली मिडकैप कंपनियों के दायरे के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें 121 कंपनियां (81 फीसदी) एक जैसी हैं। लार्जकैप के मामले में बेंचमार्क बीएसई-100 इंडेक्स के साथ यह 79 फीसदी है।

मौजूदा ढांचे के मुताबिक, मिडकैप फंडों को अपने कोष का कम से कम 65 फीसदी मिडकैप शेयरों में निवेश करना होता है, वहीं लार्जकैप फंडों को अपना 80 फीसदी लार्जकैप शेयरों में निवेश करना होता है।

सूत्रों का कहना है कि नियामक किसी निवेश श्रेणी में न्यूनतम निवेश की सीमा में बदलाव से दूर रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक, नए ढांचे का प्रभावी तौर पर मतलब यह होगा कि बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 125 अग्रणी कंपनियों को लार्जकैप के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा, वहीं 126वीं से 425वीं कंपनियों को मिडकैप के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। बाकी कंपनियां स्मॉलकैप के तौर पर वर्गीकृत होंगी।

और शेयर शामिल किए जाने से लंबी अवधि में कुछ लचीलापान मिल सकता है, लेकिन कुछ को भय है कि इससे चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कुछ का कहना है कि श्रेणी का ढांचा फंड मैनेजरों को अपना पोर्टफोलियो दोबारा समायोजित करने को बाध्य करेगा और शेयरों में बदलाव में एक और साल लग सकते हैं।

एक फंड हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस कदम से फंड मैनेजरों को एक बार फिर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। कुछ साल पहले हुए बदलाव के कारण पहले से ही कई बदलाव करने पड़े हैं।

बीएमए क्लाइंटों की मांग पर विचार नहीं करेगा एचडीएफसी बैंक

बैंक ने कहा कि ब्रोकर की तरफ से गिरवी शेयर बेचने के मामले में वह अधिकारों के दायरे में था

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 12 फरवरी

एचडीएफसी बैंक ने निवेशकों की उस याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने निलंबित ब्रोकरेज बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स की तरफ से धोखे से गिरवी रखे उनके शेयर वापस करने की मांग की गई थी।

बीएमए के क्लाइंटों ने निजी क्षेत्र के बैंक से ब्रोकरेज की तरफ से गिरवी रखे गए शेयर डिपॉजिटरी के खाते में वापस करने की मांग की थी।

बीएमए के क्लाइंटों को लिखे एक पत्र में एचडीएफसी बैंक ने कहा है, कर्ज समझौते के तहत ब्रोकरेज की तरफ से गिरवी रखे शेयर को बेचने के मामले में वह अपने अधिकारों के दायरे में है। बैंक ने कहा है कि बीएमए ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि गिरवी रखे शेयरों का मालिकाना हक उसके पास है। बैंक बीएमए के निवेशक समूह की तरफ से लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया जता रहा था।

पत्र में कहा गया है कि क्लाइंटों के पास बीएमए की दिया गया दस्तावेज है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गिरवी शेयर क्लाइंटों के हैं और एचडीएफसी बैंक से उसे न बेचने का अनुरोध किया गया। एचडीएफसी बैंक ने इस आरोप से इनकार किया है।

इस पर जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। कुछ निवेशकों ने धमकी दी है कि अगर बैंक उनके शेयर वापस नहीं करता तो वह भारतीय रिजर्व बैंक और प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) का दरवाजा खटखटाएगा। एचडीएफसी बैंक ने कहा, बैंक ऐसे किसी कदम का मजबूती से विरोध करेगा।

अक्टूबर में सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में अनियमितता के लिए बीएमए पर पाबंदी लगा दी थी। ब्रोकर के खिलाफ आरोप था कि वह क्लाइंटों की प्रतिभूतियां अलग करने में नाकाम रही, एक्सचेंज को भ्रामक सूचना दी, गिरवी शेयर छुड़ाने और भुगतान के बाद उसे क्लाइंटों को लौटाने में नाकाम रहा और क्लाइंटों के डीमैट खाते से अनधिकृत तौर पर शेयरों का हस्तांतरण किया।

सेबी के आदेश में एनएसई के एक ईमेल का जिक्र है, जिसमें बीएमए की तरफ से सामने रखे गए बैलेंस में काफी बेमेल व असंगतता देखने को मिली थी। आदेश में कहा गया था कि वास्तविक रिकॉर्ड के मुकाबले क्लाइंटों की 100 करोड़ रुपये प्रतिभूतियां कम पाई गई थी।

अंतिम आदेश में सेबी ने बीएमए को अपनी सभी परिसंपत्तियों की पूरी इन्वेंट्री मुहैया कराने को कहा था। स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि इन परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिये क्लाइंटों के फंडों में हुई कमी की भरपाई हो जाए।

संक्षेप में

1,780 करोड़ जुटाएगी नेटवर्क आई2आई

भारती एयरटेल ने बुधवार को कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक नेटवर्क आई2आई बिना परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड जारी कर 25 करोड़ डॉलर यानी 1,780 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाएगी। कंपनी ने हाल ही में 75 करोड़ डॉलर यानी करीब 5,343 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई थी। कंपनी ने बीएसई को बताया कि मॉरीशस स्थित अनुषंगी नेटवर्क आई2आई ने प्रस्तावित योजना के लिए निवेशकों से संपर्क साधा है। इस पूंजी का इस्तेमाल भारती एयरटेल का कर्ज कम करने में किया जाएगा। *भाषा*

इफ्का लैबोरेटरीज का शुद्ध लाभ 24 फीसदी बढ़ा

औषधि कंपनी इफ्का लैबोरेटरीज का एकीकृत शुद्ध लाभ 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 24.15 प्रतिशत बढ़कर 197.54 करोड़ रुपये हो गया। इफ्का लैबोरेटरीज ने कहा कि इससे पूर्व वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में कंपनी को 159.11 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 1,230.99 करोड़ रुपये रही। इफ्का लैबोरेटरीज के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर 5 रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। *भाषा*

बजाज ने उतारा पल्सर 150 का बीएस-6 संस्करण

बजाज ऑटो लिमिटेड ने लोकप्रिय मोटरसाइकिल पल्सर 150 का बीएस-6 संस्करण बुधवार को पेश किया। इसकी शोरूम कीमत 94,956 रुपये से शुरू है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसके दो संस्करण पल्सर 150 और पल्सर 150 ट्विन डिस्क पेश किए गए हैं। इनकी कीमतें क्रमश: 94,956 रुपये और 98,835 रुपये है। *भाषा*

हिंडाल्को का कर पूर्व लाभ घटा

अदिति दिवेकर
मुंबई, 12 फरवरी

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का एकीकृत कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में 1,481 करोड़ रुपये रहा, जो कमजोर राजस्व के कारण पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 23 फीसदी कम है। इस अवधि में कंपनी का राजस्व 29,197 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 12 फीसदी कम है। कमजोर मांग के कारण कंपनी के राजस्व पर असर पड़ा।

कंपनी के प्रबंध निदेशक सतीश पई ने कहा, तीसरी तिमाही में मांग क्रमिक आधार पर 13 फीसदी घटी जबकि सालाना आधार पर 5 फीसदी। एल्युमीनियम और तांबे की मांग तीसरी तिमाही में घटी। ब्लूमबर्ग ने कंपनी का राजस्व तीसरी तिमाही में 30,073 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया था।

एल्युमीमियम की उत्पादन लागत कम रहने के बावजूद कंपनी का एबिटा सालाना आधार पर 10 फीसदी घटकर 3,676 करोड़ रुपये रहा। क्रमिक आधार पर एल्युमीमियम का उत्पादन 5 फीसदी घटा, लेकिन बिक्री से मिलने वाली रकम कम रहने से एबिटा प्रभावित हुआ। तांबे की मांग भी क्रमिक आधार पर 2 फीसदी और सालाना आधार पर 8 फीसदी घटी।

एकल आधार पर कंपनी का राजस्व 14 फीसदी घटकर 10,230 करोड़ रुपये रहा जबकि कर पूर्व लाभ 307 करोड़ रुपये, जो पिछले साल की समान अवधि में 337 करोड़ रुपये रहा था।

नैटको का कर पूर्व लाभ घटा

नैटको फार्मा लिमिटेड का कर पूर्व लाभ दिसंबर तिमाही में कम राजस्व व लाभ के कारण 37 फीसदी की गिरावट के साथ 128.8 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी का कर पूर्व लाभ 204.7 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी की कुल आय 11 फीसदी घटकर 513 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 580 करोड़ रुपये रही थी। हालांकि तिमाही में कुल खर्च 2.31 फीसदी बढ़कर 384.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 375.3 करोड़ रुपये रहा था। नैटको फार्मा के प्रबंधन ने कहा कि हेपेटाइटिस-सी के पोर्टफोलियो में मार्जिन का दबाव बना रहा।

अशोक लीलैंड का कर पूर्व लाभ घटा

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 फरवरी

व्यावसायिक वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड का कर पूर्व मुनाफा चालू वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही में 89 प्रतिशत गिरावट के साथ 54.17 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वर्ष की समान अवधि में कंपनी का यह आंकड़ा 483.57 करोड़ रुपये रहा था। बिक्री गिरने की वजह से कंपनी की कुल आय में भी कमी दर्ज की गई और यह 6,346.04 करोड़ रुपये से कम होकर 4,037.98 करोड़ रुपये रह गया।

अशोक लीलैंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी विपिन सोंधी ने कहा कि व्यावसायिक वाहन उद्योग में सुस्ती बरकरार है और दिसंबर तिमाही में बिक्री में करीब 39 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। आलोच्य तिमाही में कंपनी का कारोबार भी कमजोर रहा। इसके बावजूद कंपनी 5.6 प्रतिशत की ब्याज, कर आदि पूर्व कमाई (एबिटा) हासिल करने में कामयाब रही।

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी गोपाल महादेवन ने कहा, 'इस वर्ष के शुरू में उत्पादकता बढ़ाने एवं लागत कम करने का शुरू किया गया हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। इन कदमों से हमें काफी हद तक लागत कम करने में मदद मिली है। हम नकदी प्रवाह बढ़ाने और भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं।'

दो-तीन साल में करीब 3,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी सिएट

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 12 फरवरी

टायर बनाने वाली कंपनी सिएट अगले 2-3 साल में करीब 3,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी ने आज तमिलनाडु में नए संयंत्र का उदघाटन किया, जहां रोजाना करीब 28,000 यात्री कार टायरों का उत्पादन होगा और यह आने वाले समय में कंपनी का सबसे बड़ा संयंत्र होगा।

3,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश चेन्नई, हलोल और नागपुर समेत अन्य संयंत्रों में होगा। कंपनी ने पहले हालांकि 3,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का संकेत दिया था। ऐसे में सिएट अब पहले की योजना के मुकाबले 500 करोड़ रुपये कम खर्च करेगी।

संयंत्र के उदघाटन के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक अनंत गोयनका ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, कंपनी ने चेन्नई के पास करीब 4,000 करोड़ रुपये निवेश करने को प्रतिबद्ध है, जिसमें से करीब 1,400 करोड़ रुपये निवेश किए जा चुके हैं और बाकी निवेश अगले कुछ वर्षों में किया जाएगा।

पहले चरण में नया संयंत्र पूरी क्षमता से परिचालित होने पर रोजाना करीब 28,000 यात्री कार टायरों का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा, 1,400 करोड़ रुपये के निवेश से करीब 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित होगा।

इस क्षमता का करीब 15-20 फीसदी निर्यात बाजारों के लिए होगा। आज अन्य संयंत्रों से करीब 90 से ज्यादा देशों को आपूर्ति करती है। अभी यहां करीब 300 कर्मचारी हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 की जाएगी, जिनमें 40 फीसदी महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि संयंत्र में विस्तार करने और वाणिज्यिक वाहनों का टायर बनाने के लिए पर्याप्त जगह है।

सिटी यूनियन बैंक का शुद्ध लाभ बढ़ा

सिटी यूनियन बैंक का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में 8.04 प्रतिशत बढ़कर 192.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बैंक ने बुधवार को बीएसई को बताया कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसे 178.10 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। इस दौरान बैंक की कुल आय साल भर पहले के 1,086.45 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,203.23 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। बैंक का शेयर बीएसई में 0.61 प्रतिशत गिरकर 228.75 रुपये पर चल रहा था। *भाषा*

क्यूआईपी से संबंधित शेयरों का प्रदर्शन बेहतर

दीपक कोरगांवकर
और पुनीत वाधवा
मुंबई/नई दिल्ली, 12 फरवरी

जिन निवेशकों ने क्यूआईपी के लिए आवेदन किया है उन्हें उस शेयर की बाजार कीमतों में उछाल से अच्छा खासा रिटर्न मिला है। इक्विटी बाजार में तेज सुधार से क्यूआईपी के जरिए पिछले छह महीने में रकम जुटाने वाली 12 में से 9 कंपनियों के शेयरों ने अपने इश्यू प्राइस के मुकाबले 33 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज कर बाजार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। येस बैंक (58 फीसदी नीचे), आरबीएल बैंक (5 फीसदी नीचे) और प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स (0.04 फीसदी नीचे) ही अपनी-अपनी क्यूआईपी कीमत से नीचे हैं।

इन 12 कंपनियों ने संयुक्त रूप से क्यूआईपी के जरिये करीब 49,117 करोड़ रुपये जुटाए, जिसका मूल्यांकन अभी 17 फीसदी बढ़कर 57,371 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसकी तुलना में एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में औसतन 3.8 फीसदी का रिटर्न मिला है।

एसऐंडपी बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स (23 फीसदी ऊपर) और एसऐंडपी बीएसई मिडकैप (22 फीसदी ऊपर) में 23 अगस्त 2019 के निचले स्तर से 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसकी तुलना में एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स इस अवधि में 13 फीसदी चढ़ा है।

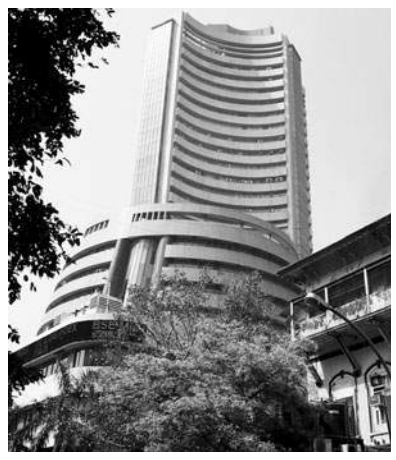

एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनैंस, श्री सीमेंट, पीवीआर, ऐक्सिस बैंक, वरुण बेवरिजेज और भारती एयरटेल अपनी क्यूआईपी कीमत से 20 से 33 फीसदी तक ऊपर है।

एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनैंस, श्री सीमेंट, पीवीआर, ऐक्सिस बैंक, वरुण बेवरिजेज और भारती एयरटेल अपनी क्यूआईपी कीमत से 20 से 33 फीसदी तक ऊपर है।

इक्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक व सीआईओ जी चोकालिंगम ने कहा, इनमें से कुछ शेयर प्रीमियम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं। क्यूआईपी के जरिए जुटाई गई रकम की लागत काफी कम है, जो अच्छी बात है। कुछ मामलों में रकम जुटाने का कोई वैकल्पिक जरिया नहीं है क्योंकि कारोबारी परिचालन शायद मजबूत नहीं है। दूसरी ओर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां क्यूआईपी के जरिये वित्तीय संसाधन अपने मूल्यांकन के सर्वोच्च स्तर पर बाजार से जुटा रही हैं।

विश्लेषकों ने कहा, इनमें कई कंपनियां मिडकैप व स्मॉलकैप की हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर उन पर भरोसा किया जाए तो इन दोनों क्षेत्रों के शेयरों में और बढ़ोतरी की गुंजाइश है।

नई ऊंचाई

इस बीच, क्यूआईपी के जरिए जुटाई गई रकम मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकती है। इस वित्त वर्ष में अब तक 13 कंपनियों ने क्यूआईपी के जरिये करीब 51,216 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस मार्ग से वित्त वर्ष 2018 में 51 कंपनियों ने रिकॉर्ड 57,524 करोड़ रुपये जुटाए थे। यह जानकारी प्राइम डेटाबेस से मिली।

हिस्सेदारी गंवा रही हैं सरकारी बीमा कंपनियां

4 बीमा कंपनियों की जनवरी 19 तक बाजार हिस्सेदारी 40.23 प्रतिशत थी, जो जनवरी 20 तक 38.2 प्रतिशत रह गई

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 12 फरवरी

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां निजी फर्मों के हाथों लगातार अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा रही हैं। आईआरडीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के हिसाब से जनवरी 2020 महीने तक 4 सरकारी जनरल बीमा कंपनियों नैशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की कुल बाजार हिस्सेदारी 38.2 प्रतिशत रह गई, जो जनवरी 2019 तक 40.23 प्रतिशत थी।

अगर न्यू इंडिया इंश्योरेंस को छोड़ दें तो अन्य तीनों कंपनियां पिछले कुछ समय से अपनी बाजार हिस्सेदारी गंवा रही हैं। बहरहाल दिसंबर 2019 की तुलना में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की बाजार हिस्सेदारी जनवरी 2020 में मामूली बढ़ी है।

जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में न्यू इंडिया इंश्योरेंस लगातार सबसे ज्यादा बाजार हिस्सेदारी वाली कंपनी बनी हुई है। जनवरी 2020 के अंत तक इसकी बाजार हिस्सेदारी 14.28 प्रतिशत थी। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की हिस्सेदारी 9.19 प्रतिशत, नैशनल इंश्योरेंस की 7.67 प्रतिशत और आईसीआईसीआई लोंबार्ड की हिस्सेदारी 7.22 प्रतिशत है।

हाल के केंद्रीय बजट में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों नैशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पुनर्पूंजीकरण के लिए 6,950 करोड़ रुपये की पूंजी की घोषणा की थी। इन तीनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी गिर रही है और खराब सॉल्वेंसी रेशियो से जूझ रही हैं।

फरवरी 2018 के बजट में सरकार ने 3 फर्मों के विलय की योजना की घोषणा की थी। इसके अलावा सरकार ने इन तीनों के विलय के बाद बनी इकाई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की योजना बनाई थी। बहरहाल उस घोषणा के बाद बहुत कम प्रगति हुई है।

आंकड़ों के मुताबिक नैशनल इंश्योरेंस का सॉल्वेंसी रेशियो वित्त वर्ष 19 के अंत तक 1.04 रहा है, जबकि नियामकीय जरूरत 1.5 की होती है। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में यूनाइटेड इंडिया का सॉल्वेंसी रेशियो 1.05 था। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी का वित्त वर्ष 202 की दूसरी तिमाही में कर भुगतान के पहले का घाटा 1,091 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2020 की पहली तिमाही में ओरिएंटल इंश्योरेंज का सॉल्वेंसी रेशियो 1.56 था। वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में कंपनी को कर के पहले का शुद्ध नुकसान 330 करोड़ रुपये था। यह तीनों बीमा कंपनियां जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जीआईपीएसए) के दारये में आती हैं जिनके विलय की योजना का खाका तैयार कनरे के लिए सलाहकार कंपनी ईवाई को नियुक्त किया गया है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ उनके विलय सहित सभी संभावनाओं पर विचार करने के बाद ईवाई ने तीन फर्मों के विलय को ज्यादा व्यावहारिक विकल्प पाया था। ईवाई ने यह भी सिफारिश की है कि विलय की प्रक्रिया दिसंबर 2020 या जुलाई से शुरू 18 महीने के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।

सरकारी बीमा कंपनियों की स्थिति

बीमा कंपनी	जन.2020 तक बाजार हिस्सेदारी	जन. 2019 तक बाजार हिस्सेदारी	दिसं. 20-19 तक बाजार हिस्सेदार
नैशनल इंश्योरेंस	7.67	8.42	7.78
ओरिएंटल इंश्योरेंस	7.06	7.72	7.09
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	9.19	9.85	8.83
न्यू इंडिया इंश्योरेंस	14.28	14.24	14.58

स्रोत : आईआरडीएआई

2,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी

भाषा
नई दिल्ली, 12 फरवरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में 2,500 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। ये तीन साधारण बीमा कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल), नैशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल) हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने इन तीनों साधारण बीमा कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय भुगतान क्षमता के उल्लंघन को देखते हुए तत्काल 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि तीनों साधारण बीमा कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति और नियामकीय कर्ज भुगतान क्षमता जरूरत को देखते हुए तत्काल 2,500 करोड़ रुपये डालने को मंजूरी दी गई है।

इन तीनों कंपनियों के मार्च 2020 के अंत तक विलय के प्रस्ताव से पहले पूंजी डालने का फैसला किया गया है। इससे पहले जनवरी में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय का काम काफी आगे बढ़ चुका है और यह कभी भी हो सकता है। मामला अभी मंत्रिमंडल में लंबित है। वित्त वर्ष 2018-19 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीनों कंपनियों के एकल बीमा कंपनी में विलय की घोषणा की थी।

विप्रो के एनआरसी ठेके का नहीं हुआ नवीकरण

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 12 फरवरी

विप्रो ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) परियोजना के लिए असम सरकार के साथ उसके काट्रैक्ट का नवीकरण नियत समय के बाद नहीं किया गया था। आईटी सेवा फर्म द्वारा मुहैया कराई गई क्लाउड स्टोरेज सेवा के कारण वेबसाइट से एनआरसी के आंकड़े गायब होने की खबरों की प्रतिक्रिया में कंपनी ने यह कहा है।

विप्रो की सफाई

बुधवार को विप्रो ने एक बयान में कहा है, 'कठिन टेंडर प्रक्रिया के बाद 2014 में विप्रो लिमिटेड को असम में राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। यह परियोजना गृह मंत्रालय के रजिस्टार जनरल आफ इंडिया द्वारा लागू की जा रही थी, जिसकी निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन थी। आईटी सेवा प्रदाता के रूप में विप्रो को परियोजना के तकनीकी आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी सॉल्यूसंस का काम दिया गया था।'

इसमें आगे कहा गया है, 'एनआरसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक ये सेवाएं मुहैया कराई गईं और इसकी निगरानी संबंधित प्राधिकारियों ने की। अक्टूबर 2019 में इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बीत जाने के बाद संबंधित प्राधिकारियों ने इसका नवीकरण नहीं किया। बहरहाल शुभेच्छा में विप्रो ने जनवरी 2020 के आखिर तक होस्टिंग सर्विस शुल्क का भुगतान किया। अगर प्राधिकारियों ने आईटी सेवा समझौते का नवीकरण किया होता तो विप्रो यह सेवाएं मुहैया कराने को तैयार थी। कंपनी इस मसले पर आगे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती है।'

सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप मे विप्रो जैसी कंपनियां क्लाउड स्टोरेज मुहैया नहीं करातीं, बल्कि वे कई वेंडरों के साथ अपने ग्राहकों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और भंडारण की जरूरतों का एकीरण करती हैं। यह अक्सर प्रोग्रामिंग या अपने दम पर सॉफ्टवेयर बनाने की तुलना में ग्राहकों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और सस्ता होता है ।

बुधवार को आई खबरों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआरसी के आंकड़े सुरक्षित थे और क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी तकनीकी खामी दूर कर ली गई है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के वरिष्ठ कर्मी का निधन

बिज़नेस स्टैंडर्ड के संपादकीय विभाग के सहायक कला निदेशक सुनील कुमार गिरोटा का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे। उन्हें मंगलवार सुबह अचानक मस्तिष्काघात के बाद नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 2008 से बिज़नेस स्टैंडर्ड में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्र और पुत्री हैं।

बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी। यह 1963 के कानून का स्थान लेगा जो देश के 12 बड़े बंदरगाहों का संचालन करता है। पोत परिवहन मंत्री मांडविया ने कहा, 'फिलहाल बंदरगाहों का संचालन 1963 के बंदरगाह कानून के जरिए होता है। मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी।' *भाषा*

रसोई गैस के दाम में 144.5 रु. प्रति सिलिंडर की भारी बढ़ोतरी

भाषा
नई दिल्ली, 12 फरवरी

रसोई गैस की कीमतों में बुधवार को 144.5 रुपए प्रति सिलिंडर की भारी-भरकम वृद्धि की गई। सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी।

हालांकि सरकार ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर दी है। इससे सब्सिडी वाले सिलिंडर के उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। कंपनियों ने कहा कि एजपीजी सिलिंडर की कीमत पहले के 714 रुपये से बढ़ाकर 858.50 रुपये कर दी गई है। यह जनवरी 2014 के बाद से रसोई गैस के भाव में हुई सबसे बड़ी वृद्धि है। तब एलपीजी का भाव 220 रुपये प्रति सिलिंडर बढ़ाकर 1,241 रुपये कर दिया गया था। सरकार ने इसके साथ ही एलपीजी सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 153.86 रुपये से बढ़ाकर 291.48 रुपए प्रति सिलिंडर कर दी है।

सब्सिडी पर उपभोक्ताओं को एक साल में 12 सिलिंडर मिलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी 174.86 रुपये से बढ़ाकर 312.48 रुपये प्रति सिलिंडर कर दी गई है। सब्सिडी के बाद एक सिलिंडर एलपीजी का भाव सामान्य उपभोक्ताओं को 567.02 रुपये तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 546.02 रुपये पड़ेगा। सामान्यत: हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के भाव में संशोधन किया जाता है। हालांकि इस बार इसमें दो सप्ताह का अधिक समय लग गया। अधिकारियों ने इस बारे में कहा कि चूंकि बड़ी वृद्धि की जानी थी, इस कारण आवश्यक मंजूरियां लेने में समय लग गया।

हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को हुए मतदान को देखते हुए रसोई गैस के दाम बढ़ाने की घोषणा टाल दी गई थी।

- जनवरी **2014** के बाद गैस के दाम में सबसे तेज बढ़ोतरी, **714** रुपये से बढ़कर **858.50** रुपये का हुआ सिलिंडर
- सब्सिडी के बाद उज्ज्वला ग्राहकों को **546.02** रुपये व सामान्य उपभोक्ता को **567.02** रुपये प्रति सिलिंडर देने होंगे

एमसीए शुरू करेगा ऑनलाइन पंजीकरण

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 12 फरवरी

कंपनी पंजीकरण की प्रक्रिया अब मौजूदा स्थिति की तुलना में बहुत अधिक आसान होने जा रही है जिसके लिए कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा मौजूदा व्यवस्था के तहत ई-फॉर्म को डाउनलोड कर उसे भरना पड़ता है जिसकी जगह नए प्रारूप में कंपनियां सीधे ऑनलाइन सारी जानकारियां भर सकेंगी जिससे उनके समय की बचत होगी।

एमसीए21 पोर्टल में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में से यह एक पहल है। इस पोर्टल में बदलाव करने की अत्यंत जरूरत महसूस की जा रही है।

इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पोर्टल के तीसरे संस्करण को लॉन्च करने के लिए एलऐंडटी इन्फोटेक का चुनाव किया है। इसके पहले और दूसरे संस्करण को क्रमश: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस ने जारी किया था।

पंजीकरण की नई प्रकिया को इन्फोसिस द्वारा लागू किया जा रहा है जिसे 15 फरवरी को जारी किए जाने का अनुमान है। नए वेब फॉर्म में इसे स्क्रीन पर ही भरने और तुरंत डेटा सत्यापन की सुविधा होगी ताकि बिना किसी झंझट के कंपनियों का पंजीकरण किया जा सके।

कंपनी सचिव गौरव पिंगले ने कहा, 'पंजीकरण की प्रक्रिया त्वरित होगी जिससे कारोबार शुरू करने में कम समय लगेगा। एमसीए की ओर से कुछ ई-फॉर्मों की मंजूरी 2 से 3 हफ्तों में भी नहीं दी जाती है। उसकी मंजूरी के लिए काफी वक्त लग जाता है।'

फिलहाल 6 एमबी के ई-फॉर्म को एमसीए21 पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। हालांकि, कंपनियों को पठनीय अटैचमेंट के साथ फॉर्म अपलोड करने में मुश्किल होती है।

पिंगले ने कहा, 'मेरे व्यक्तिगत अनुभव में लोगों द्वारा दस्तावेंजों को तलाशने पर कई तरह की दिक्कतें होती हैं। एकल लॉगइन प्रणाली में दस्तावेज खुलने में काफी समय लेता है। एक लॉग इन के लिए तीन घंटे की सीमा बढ़ाए जाने की जरूरत है।'

तीसरे संस्करण पर काम शीघ्र शुरू होने के आसार हैं। इस दिशा में लंबी अवधि की योजना में मोबाइल एप शुरू करना, रजिस्ट्रार के कार्यालय की गतिविधियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने, डेटा एनालिटिक्स फीचर लाना शामिल है लेकिन सरकार सबसे पहले अत्यंत जरूरी काम को पूरा करेगी।

सरकार प्रश्नों का जवाब देने में काफी वक्त लग जाने की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सवालों का तुरंत जवाब देने के लिए चैट बोट्स की सुविधा लाना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा लेकिन हम इसे करेंगे क्योंकि इससे कारोबारी सुगमता में सुधार आएगा।'

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंक में कारोबार शुरू करने के मानदंडों पर भारत मामूली सुधार करते हुए एक पायदान ऊपर चढ़कर 180 देशों की सूची में 136वें स्थान पर रहा था। गत वर्ष भारत के समग्र रैंक में अच्छा सुधार हुआ था और यह 77वें स्थान से सुधरकर 63वें स्थान पर आ गया था।

एक और महत्त्वपूर्ण योजना बनाई जा रही है जिसके तहत नाम पंजीकरण की प्रक्रिया को एआई आधारित किया जाएगा।

एमसीए-21 पोर्टल में किया जाएगा बदलाव

- **कंपनी पंजीकरण के लिए मंत्रालय ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है**
- **मंत्रालय ने पोर्टल के तीसरे संस्करण को लॉन्च करने के लिए एलऐंडटी इन्फोटेक का चयन किया**
- **पंजीकरण की नई प्रकिया इन्फोसिस लागू कर रही है, जिसे 15 फरवरी को जारी किए जाने का अनुमान**
- **पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस ने जारी किया था**

कोरोनावायरस का प्रकोप भारत के लिए एक मौका

अभिषेक रक्षित
कोलकाता, 12 फरवरी

केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन का कहना है कि चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते वस्तुओं व कच्चे माल की आपूर्ति में आई गिरावट भारत के लिए एक अवसर है। सुब्रमण्यन के मुताबिक भारत अपना निर्यात बढ़ा सकता है और असेंबलिंग का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है।

भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सुब्रमण्यन ने अलग से बातचीत करते हुए कहा, 'भारत निर्यात संचालित मॉडल अपना सकता है। खासककर भारत में असेंबली के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इस हिसाब से देखें तो यह अच्छा मौका है। चीन में इस समय अनिश्चितता की स्थिति है, ऐसे में भारत के लिए यह अच्छा मौका है कि वह इसका इस्तेमाल करे।'

उन्होंने कहा कि 2002 में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम से भारत बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। सुब्रमण्यन के मुताबिक चीन खुद भी शेष दुनिया से कंपोनेंट्स का आयात करता है और उसे चीन में असेंबल कर उसका निर्यात कर देता है।

उन्होंने कहा, 'अगर हम देखें कि भारत में मोबाइल विनिर्माण के मामले में क्या हो रहा है, भारत भी उसी पैटर्न का पालन कर रहा है। इस तरह से अगर आप इस नेटवर्क उत्पादों के मामले में कंपोनेंट्स के हिसाब से देखें तो यह वास्तव में हमारे लिए एक मौका है।'

> चीन दूसरे देश से कल पुर्जे मंगाता है और उससे माल तैयार करता है। इस समय भारत के पास एक मौका है कि वह इस क्षेत्र में तेजी से निर्यात बढ़ा सकता है

चीन में बीमारी के प्रकोप के कारण कुछ विनिर्माताओं ने चीन से आने वाले कच्चे माल और तैयार माल के अपने ऑर्डर रोक दिए हैं।

बहरहाल जनवरी से नए साल की छुट्टी की अवधि के दौरान फैक्टरियों में उत्पादन कम रहता है और भारत के साथ विदेशी खरीदार अपने ऑर्डर पहले बुक करते हैं और आपूर्ति में कमी के अनुमान से वे माल का भंडारण कर लेते हैं।

संस्थान में अपने व्याख्यान में अर्थशास्त्री ने कहा कि आवश्यक जिंस अधिनियम 1955 से दूरी बनाए जाने की जरूरत है, यह 'बहुत पुराना कानून' है।

हाल के प्याज और आलू की कीमतों का उदाहरण देते हुए सुब्रमण्यन ने कहा कि यह अधिनियम अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और कठिन वक्त में कीमतों पर काबू करने में असफल साबित हुआ है।

स्विगी का ब्रांडवर्क्स आया

नेहा अलावधि
नई दिल्ली, 12 फरवरी

फूड एग्रीगेटर स्विगी ने खुद से अलग पहचान के साथ केवल आपूर्ति ब्रांड तैयार करने के लिए अपने कुछ मौजूदा रेस्तरां के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने यह कदम किसी खास इलाके में खाना आपूर्ति के क्षेत्र में मौजूद अंतर को भरने के लिए उठाया है। कंपनी ने अपनी इस पहल का नाम ब्रांडवर्क्स रखा है। इसके तहत रेस्तरां के सामान्य मेन्यू से इतर विभिन्न तरह के मेन्यू, पैकेजिंग और कीमत को पेश किया गया है।

कंपनी पिछले चार से पांच महीनों से इसे प्रयोग के तौर पर चला रही थी। अब स्विगी के पास देश के 13 शहरों में 100 ब्रांडवर्क्स ब्रांड है। कंपनी की योजना साल के अंत तक इसकी संख्या को बढ़ाकर तिगुना करने की है।

कंपनी ने 13 शहरों में 100 ब्रांड उतारे, साल के अंत तक यह संख्या तिगुनी की करने की योजना

स्विगी के न्यू सप्लाई कारोबार के मुख्य कार्याधिकारी विशाल भाटिया ने कहा, 'हमने ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखकर उन रेस्तरां से संपर्क किया जिनकी रसोई क्षमता के बारे में हमे पता था। हमने उन्हें मेन्यू, चित्र, कीमत, पैकेजिंग आदि को लेकर साथ में एक ब्रांड शुरू करने की पेशकश की। ये ब्रांड साझेदारों के मौजूदा रसोइयों से बाहर परिचालित होते हैं लिहाजा यह ऐसे साझेदारों के लिए जो अपने मौजूदा रसोई से बाहर और भी कुछ करना चाहते हैं उनके लिए एक विकल्प है। इससे ग्राहकों की जरूरतें भी पूरी होती हैं।'

भाटिया ने कहा कि उदाहरण के तौर पर देखें तो दिल्ली में चीन के खाद्य पदार्थों की सुगम आपूर्ति के क्षेत्र में मौके हैं। स्विगी ने दिल्ली स्थित चीनी और थाई भोजना शृंखला बर्कोस के साथ साझेदारी की है और हाउस ऑफ चाउ नाम से केवल आपूर्ति ब्रांड शुरू किया है।

बीएस सूडोकू 3663 | परिणाम संख्या 3662

						8		
1		4	7				5	
8							4	9
		9		6				
	8	2	9	4	3	7	6	
				8		9		
3	4							7
	1				6	2		8
		6						

5	4	7	1	6	2	3	9	8
9	6	3	5	8	4	7	1	2
8	1	2	7	3	9	5	4	6
3	2	1	8	4	6	9	7	5
6	9	8	3	7	5	4	2	1
4	7	5	2	9	1	6	8	3
1	3	6	4	2	7	8	5	9
7	5	9	6	1	8	2	3	4
2	8	4	9	5	3	1	6	7

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल ★★★★☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2020/2030, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4150/4200, तिल सफेद 8900/9000, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1425/1525,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2040/2050, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4250, लालमती 3150/3200, चावल (सोना) 2700/2750,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1338, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1415, फ्लैक 1360, डीएमओ 975, टरपीन लैस बोल्ड 1430

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1060/1080, खुरपा 980/1000,चाकू 1030/1100, रसकट 880/900, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3295, बुंदकी 3270, बुढ़ाना 3300, शामली 3240,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 950/960, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4225, खल: सरसों 2150/2250, बिनौला 2250/2400, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5000/5200, गेहूं (मिल) 2120/2125, मक्की 2100/2115, बाजरा 1750/1760, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3725/3750, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4200/4225,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2100, ग्वार 3600/3650, जौ 2050/2060,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 6800/6900, बाजरा (गुजरात) 1800/1825, बाजरा (जयपुर) 1800/1825, चना 4000/4100, काबली चना 4800/6000, मूंग 7000/7100,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्याइंट)108, राइसब्रान (अखाद्य) 105, खल सरसों 1870, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1100, लाल 1100, कंटीन्यूअस 1150,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 8000/8700, अरहर दाल 7400/7900, उड़द साबुत 7300/8400, उड़द धोया 9000/9700, छिलका 8500/9200, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5300/5400,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5750/5800, सेला 5150/5200, शरबती साधारण सेला 3650/3675, शरबती स्टीम 3950/4000,चावल 1509 सेला 4800/4900, धान: शरबती 2000/2050,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4000/4050, हरियाणा 3980/4000, राजस्थान 3950/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2350/2450, सरसों खल 2000/2020,

फाजिल्का
गेहूं 2040/2050, सरसों 3900/4000 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 4300/4400, कपास नरमा (क्विं.) 5000/5250, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2200/2300,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2030/2050, चावल परमल कच्चा 2325/2365, सेला 2260/2310, मक्की यूपी 1975/2000, दाल उड़द छिलका 8600/9700, चना देशी 4725/ 4775, दाल चना 5000/5100, काबली चना 5000/5900, राजमां चित्रा पुणे 7000/8500, चीन 8500/9000,

करनाल
गेहूं दड़ा 2035/2045, बासमती चावल 6050/6150, धान 1121 नं. 2700/2750, पूसा 1509 धान 2500/2550, शरबती धान 2000/2040, सेला (1509 नं.) चावल 4800/4825, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3700/3750, जौ 1840/1850, सरसों 3800/3900, मूंग 7000/7100, गेहूं 2050/2065,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1140/1160, देशी घी (एक ली/जार) 360/460, रिफाइंड (टीन) 1480/1500,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3850/3900, खल बिनौला मोटी 2100/2200, बिनौला 2600/3100, सरसों तेल 8500/8550, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3700/3750, बाजरा 1625/1650 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 308

नि:शुल्क बिजली की राजनीति

हमारे देश में किसी भी नीति की अंतिम सराहना इस आधार पर होती है कि वह चुनावी जीत दिलाने में सक्षम है या नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पुनर्निर्वाचन के बाद देश भर के राजनेताओं, खासतौर पर राज्यों के नेताओं के सामने यह बात रेखांकित हुई होगी कि बिजली सब्सिडी की नीति कितनी उपयोगी साबित हो सकती है। दिल्ली में हर परिवार को हर माह 200 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क दी जाती है और 400 यूनिट तक की बिजली पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। कुछ अन्य राज्य भी बिजली सब्सिडी देने की शुरुआत कर चुके हैं। गत वर्ष दिसंबर में महाराष्ट्र बिजली मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि उन्होंने भी 100 यूनिट तक बिजली प्रयोग करने वाले परिवारों को नि:शुल्क बिजली देने की व्यवहार्यता का अध्ययन शुरू किया है। हालांकि उन्होंने बहुत खेद के साथ यह भी कहा कि शायद ऐसे उपभोक्ताओं की तादाद ज्यादा न हो। इस बीच पश्चिम बंगाल में जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव में करीबी मुकाबला दिख सकता है, वहां इस वर्ष के बजट में तोहफों की बहार है। इसमें शीर्ष पर 200 करोड़ रुपये की एक योजना है जिसके तहत आम परिवारों को एक तिमाही में 75 यूनिट बिजली खपत नि:शुल्क करने की बात शामिल है।

ये योजनाएं भले ही अभी प्रस्ताव के स्तर पर हों लेकिन दिल्ली की तुलना में कम महत्त्वाकांक्षी हैं। परंतु इनसे आने वाले कष्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिछले दशक की उपलब्धियों में एक यह समझ भी थी कि उपभोक्ताओं को अगर बिजली विश्वसनीय ढंग से मिले तो वे इसके लिए पैसे चुकाने को इच्छुक हैं। बिजली क्षेत्र की दिक्कतें अब मध्यस्थता की दिक्कतें हैं। उपभोक्ता पैसे देने के इच्छुक हैं और पर्याप्त बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। नीति निर्माताओं को केवल एक को दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता है। बहरहाल, हम वापस राजनीति से प्रेरित बिजली सब्सिडी की ओर लौट रहे हैं जो अब तक अर्जित लाभों को छीन सकती है। ऐसे में बिजली पारेषण सुधार असंभव भले ही नही हों लेकिन इनमें और देरी हो सकती है। राज्य बिजली बोर्डों को अभी बिजली उत्पादकों के करीब 80,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

इसके अलावा राज्य सरकारों पर कई अन्य क्षेत्रों पर खर्च करने का दबाव रहता है। इस सूची में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राथमिक शिक्षा को वरीयता प्राप्त है। बिजली सब्सिडी का वादा ध्यान आकृष्ट करता है और इससे चुनावी नारे गढ़ने में आसानी रहती है। परंतु ऐसी सब्सिडी में कोई राजनीतिक विशिष्टता नहीं है। यदि एक पार्टी 100 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली का वादा करती है तो उसका प्रतिद्वंद्वी दल 200 यूनिट तक बिजली देने का वादा कर सकता है। यानी इस तरह का लोकलुभावनवाद हमेशा ऐसी प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है जहां नीचे गिरने की होड़ होती है। इसका दीर्घकालिक लाभ किसी को नहीं मिलता। जब इसकी तुलना कड़ी मेहनत से उत्पादक श्रम शक्ति तैयार करने से किया जाता है तो इस तरह की रियायतें सार्वजनिक धन के अपव्यय से ज्यादा नहीं लगतीं।

यह बात भी ध्यान देने लायक है कि दिल्ली में भी नि:शुल्क बिजली के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि का बेहतर प्रयोग संभव है। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव का अर्थ यह है कि सरकार को इस क्षेत्र में काफी धन खर्च करना होगा। इतना ही नहीं राष्ट्रीय राजधानी के निजीकृत विद्युत वितरण नेटवर्क में पारेषण और वितरण हानि काफी हद तक कम हो गई है। इससे सब्सिडी को लक्षित करने में मदद मिलती है।

दिल्ली की वित्तीय स्थिति भी कर्जग्रस्त पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बेहतर है। ऐसे में जो रियायतें दिल्ली पर बोझ नहीं बनीं वे अन्य राज्यों में राजकोषीय कठिनाई पैदा कर सकती हैं। इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए।

विनय सिन्हा

भारत में ई-कॉमर्स की परिस्थितियां

ई-कॉमर्स की कार्य पद्धति और पारंपरिक कारोबार पर उसके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए देश में ई-कॉमर्स की गतिविधियों को लेकर विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **अजित बालकृष्णन**

यदि आप निरंतर आ रही इन खबरों को लेकर भ्रमित हैं कि एक ओर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों को भारी नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर निजी इक्विटी निवेशक बहुत बड़े पैमाने पर उनका बाजार पूंजीकरण भी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि इससे केवल आप ही भ्रमित नहीं हैं। इंटरनेट आधारित कारोबार जिस तरह चलते हैं, खासतौर पर उपभोक्ता ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबार, उन्हें चलाने का तरीका पारंपरिक कारोबारों के संचालन के तरीके से अलग होता है। इन नई प्रक्रियाओं के सामने आने के बीच देश में उपभोक्ता ई-कॉमर्स के इर्दगिर्द छिड़े विवादों को लेकर तार्किक नीतिगत रुख अपनाने में अभी काफी वक्त लगेगा।

इंटरनेट आधारित किसी भी कारोबारी मॉडल के मूल में सबसे अहम बात होती है उत्पादक या आयातक तथा उपभोक्ता या ग्राहक के बीच थोक विक्रेताओं और डीलरों की कई परतों को खत्म करना। यदि मोबाइल फोन हेडफोन की बात करें तो चीन के शेनझेन प्रांत में मौजूदा निर्माता उसे शेनझेन की किसी कंपनी को बेचता है, जिसके भारत के साथ कारोबारी संपर्क होते हैं, वह उन हेडफोन को दिल्ली में किसी कारोबारी को बेचती है जो उनका आयातक कहलाता है। इसके बाद आयातक उन हेडफोन को मुंबई (महाराष्ट्र का थोक विक्रेता) में बेच देता है। यह थोक विक्रेता अब हेडफोन को पुणे में किसी वितरक को बेचता है। उक्त वितरक हेडफोन को पुणे के विमान नगर इलाके में किसी खुदरा दुकानदार को बेचता है। इसके बाद वह ग्राहक तक पहुंचता है।

इस पूरी कड़ी को जोड़ें तो विनिर्माता से लेकर पुणे में अंतिम उपभोक्ता के बीच पांच और कड़ियां होती हैं। जब चीनी निर्माता और पुणे का उपभोक्ता इंटरनेट को अपना लेते हैं और इसके इस्तेमाल में दक्ष हो जाते हैं तो पुणे का उपभोक्ता उस हेडफोन को सीधे शेनझेन के विनिर्माता की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकता है। इस प्रकार दोनों के बीच की पांच कड़ियां गैर जरूरी हो जाती हैं। उनके लिए कोई काम ही नहीं बचा। उन्हें अपना कारोबार बंद करके सारे कर्मचारियों को निष्कासित करना होगा।

जाहिर सी बात है बीच के पांच कारोबारियों के बाहर हो जाने से चीन के निर्माता द्वारा बने हेडफोन पुणे के उपभोक्ता के लिए नाटकीय रूप से सस्ते हो जाते हैं और निर्माता का मुनाफा भी काफी बढ़ जाता है। तार्किक सोच रखने वाले इसे स्वीकार करेंगे कि किफायत का अर्थ भी यही है और यह कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहतर है।

परंतु इसका छोर कहां है? एक बात तो यह कि इस शृंखला को समाप्त करने के लिए बड़ी तादाद में ई-कॉमर्स कंपनियां सामने आ गई हैं। ये निर्माताओं और अंतिम उपभोक्ता दोनों को सब्सिडी की सुविधा देकर इसे बढ़ावा देते हैं। उन्हें आशा है कि इससे उपभोक्ता खुदरा दुकान से खरीदारी करना बंद कर देंगे और उनकी साइट को प्राथमिकता देंगे। इस सब्सिडी से नुकसान होता है लेकिन निजी पूंजी और वेंचर कैपिटल तब तक उनको नकदी मुहैया कराएंगे जब तक कि उपरोक्त शृंखला के पांचों बिचौलिया तत्त्व पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते।

भारत जैसे देशों की बात करें तो यहां यह चार स्तरीय शृंखला यानी भारतीय आयातक-राज्य स्तरीय वितरक, शहर स्तर का वितरक और दुकान, ही वह क्षेत्र है जहां आर्थिक शक्ति निहित है। इन वितरण कारोबार पर काबिज लोग ही चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब और लॉयंस क्लब आदि का नेतृत्व करते हैं और स्थानीय सहकारी बैंकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बोर्ड में होते हैं। दूसरे शब्दों मे कहें तो यही लोग देश के कारोबारी जगत के भद्र जन हैं।

दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो यह चार स्तरीय शृंखला ही जीडीपी के 30 से 40 फीसदी और देश के रोजगार में 55 फीसदी के लिए उत्तरदायी है। इस शृंखला को पूरी तरह समाप्त करने से देश में आधे रोजगार समाप्त हो जाएंगे।

उपभोक्ता व्यवहार के वे कौन से रुझान हैं जो दुनिया भर में उपभोक्ता उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों के व्यवहार को आकार दे रहे हैं? शुरुआती सवाल यह है कि सन 1990 के दशक में अपनी शुरुआत के बाद से ऑनलाइन शॉपिंग का आकार कितना बढ़ा है? इसके विश्वसनीय आंकड़े केवल अमेरिका के लिए उपलब्ध हैं: अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार सन 2019 की अंतिम तिमाही में वहां खुदरा ई-कॉमर्स बिक्री कुल खुदरा बिक्री के 10.5 फीसदी के बराबर थी। परंतु यह समग्र आंकड़ा कई गतिविधियों को छिपा लेता है। उदाहरण के लिए कई पारंपरिक ऑफलाइन डिपार्टमेंट स्टोर मसलन वॉलमार्ट आदि ऑनलाइन बिक्री बढ़ा रहे हैं। वहीं पारंपरिक रूप से ऑनलाइन रहे एमेजॉन जैसे बाजारों ने उत्पादों पर अपना लेबल लगाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन ई-कॉमर्स कुछ श्रेणियों मसलन किताबों, फैशन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में फलफूल रहा है लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसे अभी प्रभाव बनाना है।

परंतु लगातार बढ़ते ऑनलाइन उपभोक्ता आपूर्ति के लिए वसूले जाने वाले शुल्क से नाराज हैं और वे एक या दो दिन के भीतर आपूर्ति चाहते हैं। इसे हासिल करने के ऑनलाइन कंपनियां गोदामों में निवेश कर रही हैं और उद्योग पर दबदबा बरकरार रखने के लिए उन्हें आपूर्ति शुल्क और उत्पाद मूल्य पर सब्सिडी भी देनी पड़ रही है।

सब्सिडी का ऐसा इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिकी वित्तीय समुदाय में यह विश्वास है कि जो विजेता होगा, सबकुछ उसका ही होगा। यानी बाजार की शीर्ष कंपनी को सबसे अधिक मुनाफा होगा।

सन 2020 में भारत की दुविधा 19वीं सदी के आखिरी दौर में हमारे समक्ष मौजूदा दुविधा से अलग नहीं है। उस वक्त कपड़ा बनाने और बुनाई मशीनों के आगमन के बाद देश के हथकरघा बुनकरों की आजीविका खतरे में पड़ गई थी। ऐसी मशीनों के इस्तेमाल ने लोगों को बड़े पैमाने पर बेरोजगार किया था लेकिन इससे सूती कपड़ा सस्ता और जनसुलभ भी हुआ था। वह केवल जमींदारों और अमीरों के लिए सस्ता नहीं हुआ था।

उपभोक्ता ई-कॉमर्स से जुड़े विवादों से अपनी आंखें मूंद लेने का परिणाम यह हो सकता है कि यदि ई-कॉमर्स की प्रगति प्रभावित हुई तो देश की अर्थव्यवस्था कम प्रतिस्पर्धी रह जाएगी। चुनिंदा कंपनियों खासकर विदेशी कंपनियों का दबदबा होने का अर्थ राष्ट्रीय स्तर पर आत्मघाती होगा। देश के प्रतिस्पर्धा कानून में सुधार के लिए काफी प्रयास करने होंगे। इसके अलावा यदि हमें ई-कॉमर्स की पूरी क्षमताओं का लाभ लेना है तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित कानून और वेंचर फंडिंग से जुड़े कराधान कानून में भी सुधार करना होगा।

बीमारियों पर काबू पाने में मददगार होगी कृत्रिम मेधा

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

चीन के वुहान से निकलकर दुनिया भर में फैल चुका नोवेल कोरोनावायरस संक्रामक बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में कृत्रिम मेधा (एआई) के प्रभावी एवं व्यापक इस्तेमाल के लिए एक प्रायोगिक मामला होगा। इस नई बीमारी के बारे में आगाह करने वाले शुरुआती लोगों के साथ एआई भी शामिल था। इस बीमारी के संभावित वाहकों एवं पीड़ितों की शिनाख्त एवं अलगाव और उसके अनुमानित असर से संबंधित आंकड़ों से जानकारी जुटाने में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई के जरिये इसकी वैक्सीन तैयार करने और मौजूदा दवाओं की पहचान की कोशिशें भी की जा रही हैं।

उपलब्ध खबरों एवं आंकड़ों का एआई से विश्लेषण करने वाली कनाडा की कंपनी ब्लूडॉट ने कोरोनावायरस को लेकर शुरुआती चेतावनियां जारी की थीं। कई देशों के कारोबारी एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी इसके ग्राहक हैं।

ब्लूडॉट ने गत 31 दिसंबर को जारी एक परामर्श में कहा था कि यात्रियों को वुहान शहर जाने से परहेज करना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी गत 9 जनवरी को ऐसा ही एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जबकि अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र ने अपनी पहली चेतावनी 6 जनवरी को जारी की थी। ब्लूडॉट एआई ने एयरलाइंस के वैश्विक टिकट आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस वायरस के बैंकॉक, सोल, ताइपे और टोक्यो तक पहुंच जाने के बारे में एकदम सटीक अनुमान लगाए। इसके पहले ब्लूडॉट ने फ्लोरिडा में जिका वायरस के फैलने के बारे में भी ऐसा ही सटीक अनुमान लगाया था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय टीम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पोस्ट, समाचार रिपोर्ट, सरकारी स्वास्थ्य माध्यमों से मिले आंकड़े और डॉक्टरों से मिली सूचनाओं का विश्लेषण करती है ताकि वायरस के प्रसार से जुड़े लक्षण पता लगाए जा सकें।

संभावित संक्रमण के फुटप्रिंट पर कुछ एआई-आधारित अनुमान बेहद डरावने हैं लेकिन उनके गलत होने की ही संभावना अधिक है। वित्तीय तकनीक कंपनी हेजचैटर ने एक तटस्थ नेटवर्क बनाया है जो संक्रमित लोगों की संख्या, भौगोलिक विस्तार और मौतों के आंकड़े का दैनिक आधार पर पूर्वानुमान लगा सके। फरवरी की शुरुआत तक यह मॉडल वास्तविक संख्या से महज तीन फीसदी ही फर्क रहा।

यह बताता है कि अगले 45 दिनों में दुनिया की कुल सात अरब आबादी में से करीब 2.5 अरब लोग इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और मरने वालों की संख्या 5.2 करोड़ के भयानक स्तर तक जा सकती है। हालांकि ऐसा तभी हो सकता है जब इस बीमारी के प्रसार से संबंधित हालात और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया बदलती नहीं है। खतरे की घंटी बज जाने के बाद पूरी संभावना है कि संक्रमित एवं मृतकों की संख्या काफी कम रहेगी क्योंकि हालात में तेजी से बदलाव आया है।

चीन के अधिकारियों ने भी आंकड़ों को खंगालने के लिए एआई का इस्तेमाल किया है। इसके बाद एक पूरे प्रांत में रहने वाले करीब 4.5 करोड़ लोगों की घेराबंदी कर दी गई है। अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों की यात्रा करने वाले लोगों को भी निषिद्ध कर दिया है। प्रशासन ने ऐसे मोबाइल ऐप जारी किए हैं जिनकी मदद से लोग यह पता कर सकते हैं कि किसी बस, ट्रेन या विमान में यात्रा के दौरान कोई पुष्ट संक्रमित व्यक्ति तो उसमें नहीं सवार है। निश्चित रूप से यह सब चीन की साम्यवादी व्यवस्था के सख्त निगरानी इंतजामों के कारण ही संभव हो पाया है जिसमें किसी नागरिक की निजता के उल्लंघन को लेकर कोई फिक्र नहीं होती है।

गूगल की तरह चीन में लोकप्रिय सर्च इंजन बायडू ने एक प्रणाली लागू की है जो इन्फ्रारेड और चेहरा पहचान तकनीक का इस्तेमाल कर यह पता लगाती है कि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक तो नहीं है। उसने एक मिनट में 200 से अधिक लोगों की पड़ताल करने का दावा किया है जो हवाईअड्डों पर लगे थर्मल स्कैनरों से काफी तेज है।

मेडिकल शोध के मोर्चे पर चीन ने इस बीमारी की जीनोम-संरचना जारी कर दी है। इस जीनोम के कई संस्करणों का भी पता चला है और चीन के बाहर भी उनकी मौजूदगी मिली है। एआई से यह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि पहले से उपलब्ध दवाएं इस बीमारी के इलाज में कितनी कारगर हो सकती हैं? ब्रिटिश स्टार्टअप बेनेवलेंट एआई और कोरियाई दवा कंपनी डियरजेन दोनों ने इस वायरस पर असर करने वाली दवाओं की शिनाख्त करने की कोशिश की है। अमेरिकी दवा कंपनी गिलीयड भी ऐसी कोशिश कर रही है।

ऐसे मामलों में एआई ने मेडिकल आंकड़ों और वैज्ञानिक शोधपत्रों को खंगालकर असरकारक दवाएं पता करने की कोशिश की। कई दूसरी कंपनियों ने भी यही तरीका अपनाया है और अब तक ऐसी 10 दवाओं की सूची बनाई जा चुकी है जिनका परीक्षण जल्द ही शुरू होने जा रहा है।

अमेरिका-आधारित जैव-प्रौद्योगिकी कंपनी इंसिलिको ने नए अणुओं की पहचान एवं सृजन के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही है जिनका इस्तेमाल संभावित इलाज में किया जा सके। इसका मकसद ऐसे करीब 100 नए अणुओं का संश्लेषण एवं परीक्षण करना है। इंसिलिको के एआई को मेडिकल संभावनाओं वाले नए अणुओं की पहचान करने में महज चार दिन ही लगे। इंसिलिको ने इन सभी नए अणु संरचनाओं को प्रकाशित करने की बात कही है।

एआई के चलते उस जरूरी समय सीमा को घटाकर महज कुछ दिनों का कर दिया है जबकि पहले ऐसी गंभीर बीमारियों के इलाज खोजने में कई महीने और साल लग जाते थे। किसी महामारी के समय तो यह और भी जरूरी हो जाता है। आज का बेहद तेज संपर्क वाला दौर बीमारियों को भी बहुत तेजी से फैला सकता है और एआई प्रणाली इस खतरे को दूर करने का एक तरीका हो सकता है।

कानाफूसी

चड्ढा बनेंगे मंत्री

आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद दिल्ली के अगले मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों की मानें तो राजेंद्र नगर सीट से चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के उभरते सितारे राघव चड्ढा को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 31 वर्ष के चड्ढा, 38 वर्ष की अतिशी मार्लेना के साथ पार्टी का युवा चेहरा हैं। चड्ढा पेशे से सनदी लेखाकार हैं और सुनने में आ रहा है कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल यह मंत्रालय उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास है। इससे पहले वर्ष 2016 के बजट की तैयारी के वक्त चड्ढा बजट तैयार करने में उनकी सहायता कर रहे थे। उन्हें सिसोदिया का सहायक नियुक्त किया गया था। हालांकि अप्रैल 2018 में गृह मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था। परंतु एक वर्ष पहले उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया था।

हंसे या रोएं?

दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस और उसके समर्थक तय नहीं कर पा रहे थे कि खुश होना है या दुखी। पार्टी के नेता खुश थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। पार्टी को 5 फीसदी वोटों का भी नुकसान हुआ। दिल्ली मामलों के प्रभारी पीसी चाको ने कहा कि कांग्रेस इस बात से प्रसन्न है कि भाजपा का जहरीला प्रचार अभियान लोगों द्वारा पराजित कर दिया गया। कांग्रेस आमतौर पर शाम चार बजे अपना संवाददाता सम्मेलन आयोजित करती है लेकिन मंगलवार को अपराह्न एक बजे ही उसने संवाददाताओं को संबोधित कर दिया। पी चिदंबरम जैसे कांग्रेस नेताओं ने आप के प्रदर्शन की सराहना की और कहा कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा के ध्रुवीकरण करने वाले, विभाजनकारी और खतरनाक एजेंडे को नकार दिया है।

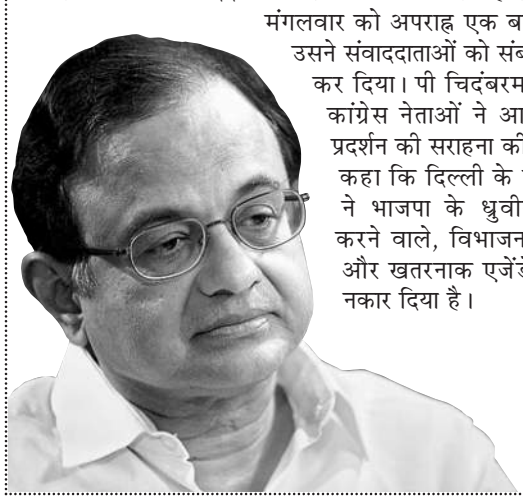

आपका पक्ष

संकट की घड़ी में चीन का साथ दें

दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई बीमारी महामारी का रूप लेती है या दो देशों के बीच युद्ध होता है, तो यह अवश्य ही दुनिया के लगभग सभी देशों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। चीन में फैले कोरोनावायरस के कारण अबतक कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से भारत में वायरस फैलने से रोकने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत को चीन से आयात बंद कर देना चाहिए। भारत जिन चीजों का आयात चीन से करता है, अगर उसका उत्पादन भारत में ही किया गया होता तो आज भारत को चीन में फैले कोरोनावायरस के समय उन चीजों की कमी नहीं खलती। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो तकनीक चीन के पास है, वह फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर हम यह सोचने लगें कि हम दूसरे देशों से कुछ भी आयात नहीं करेंगे और अगर यही बात दुनिया के दूसरे देश भी सोचने लगे तो भारत अपनी जरूरत की वस्तुओं का आयात कैसे करेगा। वहीं भारत उन चीजों की पूर्ति कैसे करेगा जिसका यहां उत्पादन होता है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकेगी। इसलिए जब हमारे पड़ोसी देश या अन्य देशों पर कोई आपदा आए तो हमें उससे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करने के लिए तरीकों पर बल देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

चीन में कोरोनावायरस फैलने के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है

लोगों की उम्मीदें निराशा में बदली

इस साल के आम बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं होने के बावजूद यह साफ है कि सरकार ने आम लोगों के साथ-साथ कारोबार जगत का भरोसा बढ़ाने वाले कई कदम उठाए हैं। इस वर्ष बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे अधिक जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा कृषि क्षेत्र पर दिया गया है। बजट में छोटे-मझोले उद्योगों को राहत देने के लिए सरकार ने सीमा शुल्क में कटौती का जो कदम उठाया है, उससे घरेलू बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद जरूर बन सकती है। हालांकि बजट में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को कम करने पर जोर नहीं दिया गया है जिससे लोग निराश जरूर हुए हैं। सरकार को बजट में महंगाई को काबू में करने और रोजगार सृजन के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि बेरोजगारी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। बजट में नई कर व्यवस्था का समावेश करते हुए अब जिस तरह से दो नई कर व्यवस्था बनाई गई है, वह राहत देने के बजाय संकट उत्पन्न करने वाला न बने। इसके अलावा खनन, ऊर्जा, रियल एस्टेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों को रफ्तार देने के लिए बजट से जिस तरह के उपायों की उम्मीद थी, उससे कारोबारी निराश ही हुए हैं। मांग, निवेश और खपत का चक्र चल निकले, रोजगार बढ़े, इसके लिए बजट में ठोस समाधान नहीं देखने को नहीं मिला है। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में आई भारी गिरावट से लोगों ने बजट को कितना पसंद किया इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस बार लोगों ने आम बजट से काफी उम्मीदें लगा रखी थी जो अब निराशा में बदल गई हैं।

कुमारी कबिता, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

रबी अनाज का उत्पादन बढ़ने का अनुमान

उत्तर पूर्वी मॉनसून (अक्टूबर से दिसंबर) में सामान्य से अधिक बारिश के बाद मिट्टी की बेहतर नमी वाली स्थिति के चलते वर्ष 2019-20 में रबी फसल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.52 प्रतिशत बढ़कर 13 करोड़ 42 लाख टन होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

नैशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन (एनबीएचसी) के रबी फसल अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2018-19 में कुल रबी अनाज उत्पादन 12 करोड़ 84 लाख टन रहा था। इस दौरान गेहूं का रकबा 12.03 प्रतिशत बढ़कर 3.34 करोड़ लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 9.01 प्रतिशत बढ़कर 11 करोड़ 14 लाख टन होने का अनुमान है। हालांकि, रबी धान का रकबा 23.24 प्रतिशत घटकर 26.1 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है, जो पिछले साल 34 लाख हेक्टेयर था।

दाल और गेहूं पर ध्यान केंद्रित करने से धान उत्पादन 27.96 प्रतिशत घटकर 1.03 करोड़ टन रहने की संभावना है। इससे पिछले वर्ष रबी मौसम में धान उत्पादन 1.43 करोड़ टन रहा था। वर्ष 2019-20 में मोटे अनाज का कुल उत्पादन 4.92 प्रतिशत बढ़कर 1.25 लाख टन हो जाने का अनुमान है। ज्वार (24.3 लाख टन), मक्का (82.8 लाख टन) और जौ (18.3 लाख टन) के उत्पादन में वृद्धि की संभावना है।

कुल मिलाकर, दलहन रकबा पिछले साल के 1.56 करोड़ हेक्टेयर से 1.86 प्रतिशत बढ़कर 1.59 करोड़ हेक्टेयर होने का अनुमान है। हालांकि, दलहन उत्पादन 2.47 प्रतिशत घटकर एक करोड़ 52 लाख टन रहने की उम्मीद है, जबकि चने का रकबा और उत्पादन क्रमशः 10.14 प्रतिशत (एक करोड़ 60 लाख हेक्टेयर) और 7.90 प्रतिशत (एक करोड़ 90 लाख टन) बढ़ने का अनुमान है। *भाषा*

आभूषण निर्यात में गिरावट जारी

चीन में कोरोनावायरस के कारण इस क्षेत्र पर भविष्य में भी पड़ सकता है असर

राजेश भयानी
मुंबई, 12 फरवरी

लुढ़का निर्यात

- जनवरी में इस क्षेत्र का कुल निर्यात 9.17 प्रतिशत गिरकर 296.64 करोड़ डॉलर रहा
- इस क्षेत्र से होने वाला पहले 10 महीनों का निर्यात भी 5.68 प्रतिशत लुढ़ककर 30.66 अरब डॉलर रहा
- जनवरी में तराशे हुए हीरों का निर्यात 5.67 प्रतिशत गिरकर 1.65 अरब डॉलर रह गया
- हॉन्गकॉन्ग में होने वाले प्रमुख निर्यात कार्यक्रम टलने से भविष्य में भी सुधार की नहीं दिख रही कोई उम्मीद
- हॉन्गकॉन्ग में विरोध प्रदर्शन और कोरोनावायरस के कारण बहुत से निर्यातकों को आमदनी की समस्या का करना पड़ रहा है सामना

रत्नाभूषण निर्यातकों की कुछेक महीने रहने वाली त्योहारी चमक खत्म हो चुकी है और जनवरी में इस क्षेत्र का कुल निर्यात 9.17 प्रतिशत गिरकर 296.64 करोड़ डॉलर रह गया। यहां तक कि इस क्षेत्र से होने वाला पहले 10 महीनों का निर्यात भी 5.68 प्रतिशत लुढ़ककर 30.66 अरब डॉलर रहा है।

हॉन्गकॉन्ग में होने वाले प्रमुख निर्यात कार्यक्रम टलने से इसके भावी परिदृश्य में भी सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। भारत से रत्नाभूषण निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ये कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण थे।

जहां एक ओर तराशे हुए हीरों के निर्यात में गिरावट का सफर जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खंडों में शुमार स्वर्णाभूषण निर्यात भी जनवरी में 2.96 प्रतिशत गिरकर 88.91 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि पहले 10 महीने में यह 4.17 प्रतिशत बढ़कर 10.21 अरब डॉलर रहा।

तराशे हुए हीरों का निर्यात जनवरी 2020 में 5.67 प्रतिशत गिरकर 1.65 अरब डॉलर रह गया और पहले 10 महीने में यह 16.80 प्रतिशत गिरकर 16.32 अरब डॉलर रहा। पहले 10 महीने में कच्चे हीरों का आयात भी 15.54 प्रतिशत गिरकर 10.92 अरब डॉलर रह गया।

रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के वाइस चेयरमैन कोलिन शाह ने कहा कि उद्योग के निर्यात में गिरावट का यह रुख जारी है। हमें आशा है कि सीमा शुल्क में जिस नीतिगत राहत की हम उम्मीद कर रहे हैं, वह बजट के बाद मिल जाएगी। हमें यह भी उम्मीद है ई-कॉमर्स नीति, व्यापक स्वर्ण नीति और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम में जिस संशोधन के लिए हमने अनुरोध किया है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसमें सुधार हो सके।

> 'उद्योग के निर्यात में गिरावट का यह रुख जारी है। हमें आशा है कि सीमा शुल्क में जिस नीतिगत राहत की हम उम्मीद कर रहे हैं, वह बजट के बाद मिल जाएगी'
>
> **कोलिन शाह**
> वाइस चेयरमैन, जीजेईपीसी

जीजेईपीसी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए मानदंडों में राहत देने लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में आभूषण खंड की चीन की कंपनियों को भारत में आकर्षित करने की बड़ी संभावना है। पहले अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का डर था और अब कोरोनावायरस का डर है।

चीन में केंद्रित विदेशी कंपनियों के लिए अपने आधार में विविधता लाने के लिए ये घटनाक्रम काफी हैं। परिषद ने कच्चे हीरे पर शुल्क छूट देने का भी अनुरोध किया है। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान चांदी के आभूषणों का निर्यात 78.14 प्रतिशत बढ़कर 1.22 अरब डॉलर हो गया। इस अवधि में रत्नों का निर्यात 9.53 प्रतिशत गिरकर 28.99 करोड़ डॉलर रह गया।

बजट प्रस्ताव में रत्नों पर आयात शुल्क बढ़ाने से परिदृश्य और बिगड़ सकता है। परिषद ने इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए भी वित्त मंत्रालय के सामने अपनी बात रखी है।

इस क्षेत्र को कोरोनावायरस की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप हॉन्गकॉन्ग का निर्यात कार्यक्रम मार्च से स्थगित करके मई में कर दिया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण था। पहले हॉन्गकॉन्ग का विरोध प्रदर्शन और अब चीन की इस महामारी के कारण बहुत से निर्यातकों को आमदनी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। उद्योग ने इस मुद्दे पर विचार करने और उचित राहत देने के लिए सरकार के सामने अपने बात रखी है।

सराफा के अधिक दामों की वजह से स्वर्णाभूषणों की बिक्री गिरी

वैलेन्टाइंस डे पर युवाओं को भा रहे चांदी के गहने

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 12 फरवरी

वैलेन्टाइंस डे पर खास तैयारी

- वैलेन्टाइंस डे पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आकर्षक रत्न जड़े चांदी के डिजाइनर गहने पेश कर रहे विनिर्माता
- वैलेन्टाइंस डे पर औसत दाम वाले पेंडेंट और अंगूठी जैसे गहनों की भी हो रही बिक्री
- आभूषणों को किफायती बनाने के लिए औसत बिक्री मूल्य में कटौती कर 10,000 से 15,000 रुपये के दायरे में चांदी के भारी दिखने वाले रत्न जड़ित आभूषण पेश कर रहे जौहरी

सोने के रिकॉर्ड शीर्ष दामों के कारण क्रिसमस से शुरू होकर 8 मार्च को मातृ दिवस के साथ समाप्त होने वाले इस 10 सप्ताह के सीजन में न केवल औसत मध्य वर्ग, बल्कि उच्च और अति उच्च वर्ग के उपभोक्ताओं के बीच अब तक खरीद की धारणा कमजोर रही है।

जहां एक ओर औसत मध्य वर्ग ने सराफा खरीद के लिए नए ऑर्डर देने बंद कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग इस वैलेन्टाइंस डे पर चांदी के डिजाइनर गहनों और सोने के कम कीमत वाले हस्तनिर्मित गहने पसंद कर रहे हैं।

चेन्नई स्थित खुदरा विक्रेता एनएसी ज्वैलर्स के प्रबंध निदेशक अनंत पद्मनाभन ने कहा कि इस वैलेन्टाइंस डे के लिए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई आभूषण विनिर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं ने आकर्षक रत्न जड़े चांदी के डिजाइनर गहने पेश किए हैं। रत्न जड़े और परिष्कृत रूप से तैयार चांदी के डिजाइनर गहने इस सीजन में युवा जोड़ों की पसंद बने हुए हैं। इसके अलावा इस वैलेन्टाइंस डे पर औसत दाम वाले पेंडेंट और अंगूठी जैसे गहनों की भी बिक्री हो रही है, लेकिन यह बिक्री चांदी के गहनों के बराबर नहीं है। नए डिजाइन वाले आभूषणों के साथ जौहरियों ने वैलेन्टाइंस डे के लिए अपने संभावित ग्राहकों के तौर पर युवा वर्ग को लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है। आभूषणों को किफायती बनाने के लिए औसत बिक्री मूल्य में कटौती करते हुए जौहरियों ने 10,000 से 15,000 रुपये के दायरे में चांदी के भारी दिखने वाले रत्न जड़ित आभूषण पेश किए हैं।

स्वारोवस्कि इंडिया के प्रबंध निदेशक (रत्न) राजेंद्र जैन ने कहा कि कई ब्रांड नए आभूषणों के जरिये युवा वर्ग को लक्ष्य बना रहे हैं। केवल एक सीजन की अपेक्षा जौहरी उपभोक्ताओं की बार-बार की जाने वाली खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैन ने कहा कि हालांकि इस साल सोने के दामों में तीव्र इजाफे के कारण उपभोक्ताओं का रुख चांदी की ओर हो गया है, लेकिन चांदी के सादे गहनों के बजाय उपभोक्ता किसी खास मौके और रोजमर्रा पहने जाने वाले डिजाइनर गहने तलाश रहे हैं।

सोने के दाम 40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड शीर्ष स्तर तक पहुंच चुके हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के साथ-साथ आर्थिक मंदी ने सराफा को सुरक्षित निवेश वाली परिसंपत्ति बना दिया है। अलबत्ता चांदी का भाव 46,100 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। यह उपभोक्ताओं को भारी धनराशि व्यय किए बिना मूल्यवान धातु खरीदने के गर्व का अनुभव करा रही है। हाल ही में 50,000 रुपये प्रति किलोग्राम की मनोवैज्ञानिक सीमा पार करने के बाद चांदी के दाम घटने लगे हैं। इस बीच गौतम बनर्जी, राजीव पोपली तथा रियाज गंगजी जैसे आभूषण और फैशन डिजाइनरों ने इस वैलेन्टाइंस डे पर फैशन सामग्री और मूल्यवान धातु में आकर्षक डिजाइन पेश किए हैं। पिछले साल तक 10 प्रतिशत सीमा शुल्क और इसके बाद 12.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि के कारण भारत में आभूषण बिक्री में पिछले तीन से चार सालों के दौरान लगातार गिरावट देखी गई है। इसके अलावा सरकार ने कच्चे और तराशे हीरों पर क्रमशः 2.5 फीसदी और 7.5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगा दिया है। साथ ही सरकार ने रत्नों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया है और गहनों के प्रमाण-पत्र और हॉलमार्किंग पर 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लगा दिया है। इससे हालात बदतर हो गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Feb 12	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,689.5	-4.3	1,976.5	3.1
Copper	5,696.0	-2.4	6,335.9	3.1
Nickel	13,100.0	-15.5	13,666.9	-19.3
Lead	1,820.0	-12.4	2,102.6	-1.8
Tin	16,380.0	-0.5	17,409.6	0.3
Zinc	2,145.0	-15.6	2,411.0	-13.4
Gold ($/ounce)	1,565.8*	7.5	1,762.3	6.6
Silver ($/ounce)	17.6*	4.7	19.9	3.3
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	55.2*	-11.8	53.2	-15.0
Natural Gas ($/mmBtu)	1.8*	-30.5	1.8	-30.7
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	195.2	5.9	290.9	-1.8
Maize	181.9*	0.9	256.0	-7.1
Sugar	447.0*	36.5	487.9	0.2
Palm oil	697.5	9.8	1,130.2	12.2
Rubber	1,289.4*	-13.5	1,930.9	7.8
Coffee Robusta	1,280.0*	-4.0	1,808.2	-4.6
Cotton	1,504.4	5.4	1,574.9	0.4

* As on Feb 12, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	40.0	38296
Oil and Oilseeds	350.6	82411
Spices	1.1	9
Metal(Feb 11)		
Metal- non ferrous	5385.5	48056
Metal- precious	9575.0	407
Oil and gas(Feb 11)		
Gas	2203.7	55750
Oil	16016.5	3111

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	146.6	131425
Grains	192.1	93060
Oil and Oilseeds	755.9	422025
Others	137.5	63060
Pulses	162.8	44195
Spices	46.0	21637

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Lead Mini (Feb 28)	146.0	2.2
Aluminium Mini (Feb 28)	138.3	1.4
Lead (May 29)	147.6	1.2
Crude Oil (Feb 19)	3580.0	1.1
Copper (Feb 28)	433.8	1.1
Nickel (Feb 28)	952.1	1.0
Losers (* % Change)		
Cardamom (Mar 13)	3517.1	-2.7
Mentha Oil (Feb 28)	1162.6	-2.2
Silver Mini (Feb 28)	45677.0	-1.2
Silver Micro (Feb 28)	45687.0	-1.2
Silver (Mar 05)	45664.0	-1.2
Gold (Apr 03)	40410.0	-0.7

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Losers (* % Change)		
Coriander-Kota (Apr 20)	6263.0	2.6
Chana-Bikaner (Mar 20)	4017.0	2.4
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1810.0	2.2
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4051.0	1.9
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	6832.0	1.7
Guar Seed 10 (Feb 20)	3890.0	1.3
Soyabean Indore (Feb 20)	3964.0	1.0
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	3858.0	0.5
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1062.0	0.5
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	847.0	0.5
Jeera Unjha (Mar 20)	13680.0	0.3
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5882.0	0.0

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Apr 30)	1062.0	4.0
Cotton-Rajkot (Feb 28)	19100.0	1.3
Aluminium Mum (May 29)	140.0	0.3
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	45687.0	0.1
Silver Ahm (Mar 05)	45664.0	0.0
Zinc Mumbai (May 29)	171.7	0.0
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Feb 28)	1162.6	-11.1
Cardamom Vandanmedu (Feb 14)	3499.2	-7.1
Lead Min Mumbai (Feb 28)	146.0	-2.7
Nickel Mumbai (Feb 28)	952.1	-2.2
Zinc Mini Mumbai (Feb 28)	168.3	-1.9
Lead Mum (May 29)	147.6	-1.6

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1915.0	5.9
Bajra-Delhi (Feb 20)	1915.0	3.0
Crude Palm Oil Kandl (Feb 28)	722.3	2.3
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	5882.0	1.3
Maize-Sangli (Feb 20)	1826.0	1.1
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	18860.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1690.0	-20.9
Jeera Unjha (Mar 20)	13680.0	-4.6
Soy Bean Indore (Feb 20)	3964.0	-2.6
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	6832.0	-1.4
Moong-Merta City (Feb 20)	7573.0	-0.4

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai	
Aluminium utensil scrap /kg	105	(105)
Aluminium ingots /kg	141	(141)
Brass sheet cutting /kg	328	(326)
Brass utensil scraps/kg	311	(311)
Copper heavy scrap /kg	418	(417)
Copper utensil scraps/kg	394	(392)
Copper wire bar /kg	452	(450)
Lead ingots /kg	150	(150)
Nickel Cathodes /kg	975	(980)
Tin slabs /kg	1242	(1240)
Zinc slabs /kg	172	(172)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai	
Bengal Deshi /Qtl	10151	(10151)
DCH - 32 /Qtl	11332	(11332)
Jaydhar /Qtl	9758	(9758)
Shankar- 6 /Qtl	11079	(11079)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai	
Castor FSG /10kg	835	(831)
Castor Comm /10kg	825	(821)
Ricebran oil/10kg	820	(820)
Groundnut oil /10kg	1140	(1140)
Linseed oil /10kg	900	(900)
Karanji /10kg	800	(800)
Palm oil /10kg	830	(840)
Sunflower exp ref /10kg	875	(880)
Sunflower oil exp /10kg	820	(825)
Soyabean ref / 10kg	842	(850)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai	
Mumbai M-30 /Qtl	3360-3602	(3390-3602)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel		
NYSE Crude	50.73	(49.94)
Brent Crude (UK)	55.05	(54.03)
Brent Crude (WTI)	49.94	(49.94)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	1.82	(1.79)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	293.8	(290.12)
Naptha spot /Rs/MT	45170	(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150	(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950	(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai	
Standard (99.50 Purity) /10 gms	40421	(40461)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	40583	(40624)
Silver.999/ kg	45675	(46025)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18825.95	18803.90
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.80	139.65
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1855.00	1860.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1827.10	1807.50
Barley Jaipur (N)	1 Q	2135.85	2135.85
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3817.00	3787.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	3972.60	3979.75
Castor Seed-Kadi (N)	X	3967.50	3975.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	3990.20	4019.25
Chana Delhi (N)	1 Q	4210.70	4235.45
Chana-Akola (N)	X	3925.00	4025.00
Coriander-Gondal (N)	X	6100.00	6075.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6140.00	6185.55
Coriander-Kota (N)	1 Q	6274.75	6257.75
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	1833.50	1865.85
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	1888.90	1902.70
Cotton-Kadi (N)	1 B	18832.80	18814.85
CPO-Kandla (M)	10 K	749.80	744.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	720.40	706.25
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	730.00	725.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	904.50	904.85
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1547.45	1548.65
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3452.55	3455.15
Gold Ahm (M)	10 G	40468.00	40467.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32505.00	32504.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4058.00	4055.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	6866.30	6932.15
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3867.85	3900.00
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3800.00	3875.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1100.50	1097.25
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	103.80	103.70
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	14850.00	14900.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	14325.00	14343.20
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	823.90	821.00
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1011.00	1013.25
Kapas-Rajkot (N)	X	1008.65	1006.65
Lead Mum (M)	1 K	151.40	150.05
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1860.00	1855.65
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2041.50	2045.00
Maize-Erode (N)	X	1833.75	1850.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	2041.50	2045.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2010.00	2025.00
Maize-Sangli (N)	X	1823.35	1805.90
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4650.00	4650.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7562.50	7600.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4282.50	4231.00
Nickel Mumbai (M)	1 K	982.10	973.30
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3100.00	3100.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3152.00	3154.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	331.65	332.15
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33250.00	33436.35
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	820.00	817.50
Rape mustards-Patan (I)	20 K	755.00	763.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1875.65	1885.75
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5366.65	5318.30
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	811.40	806.25
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	855.00	850.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	859.25	851.90
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	855.00	850.00
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13700.00	13775.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13667.00	13750.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	45961.00	45644.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4080.00	4070.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	3939.00	3919.50
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4173.85	4151.10
Soy Bean-Akola (N)	X	4095.00	4040.00
Soymeal Indore (N)	1 T	32500.00	32400.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	855.00	851.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31000.00	31000.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31020.00	31020.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28530.00	28530.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3235.00	3240.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3361.90	3366.65
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3293.65	3288.15
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3466.65	3461.90
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3267.05	3259.35
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3151.65	3148.75
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5878.15	5806.25
Wheat Delhi (N)	1 Q	2206.65	2202.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2186.90	2175.55
Wheat New Indore (N)	1 Q	2187.50	2187.50
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2090.00	2120.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2205.00	2212.50
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5500.00	5475.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5800.00	5750.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	170.60	171.60

* as on Feb 11, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (बुधवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19120, 19120, 19000, 19100	2194	351	26845
Mar 31	19360, 19380, 19250, 19370	910	161	9014
Apr 30	19600, 19630, 19550, 19620	119	28	1429
Jun 30	19800, 19800, 19800, 19800	04	1	04
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	1775, 1812, 1770, 1810	9910	642	23350
Mar 20	1799, 1834, 1789, 1830	47730	3263	78390
Apr 20	1824, 1857, 1814, 1855	6370	540	19920
May 20	1846, 1884, 1846, 1871	880	68	5870
Jun 19	-, 1881, -, 1881	20	1	620
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1055, 1064.5, 1055, 1062	684	106	992
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1055.5, 1064, 1053.5, 1062	1344	668	3275
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3848, 3908, 3802, 3890	7875	814	11490
Mar 20	3892, 3948, 3836, 3930	39335	4374	71780
Apr 20	3916, 3976, 3886, 3962	2015	230	4960
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	3822, 3862, 3818, 3858	1645	205	5745
Mar 20	3860, 3900, 3850, 3888	4835	540	21830
Apr 20	3876, 3928, 3870, 3920	655	98	5875
May 20	3926, 3928, 3918, 3918	20	4	20
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	727.2, 735.8, 722.1, 733.4	21810	1601	43030
Mar 31	720, 729.1, 715.6, 727	20130	1192	30570
Apr 30	712, 725.2, 711.6, 723.3	1800	113	8550
Mentha Oil MCX(1 K)				
Feb 28	1182, 1182, 1160, 1162.6	217.8	515	173.88
Mar 31	1172.3, 1173.9, 1157.1, 1161.3	70.92	154	83.88
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3955, 4060, 3955, 4051	3810	283	4320
Apr 20	3990, 4064, 3975, 4054	21000	1682	17370
May 20	4015, 4080, 4010, 4072	1800	158	3810
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	843.6, 847.8, 840.8, 847	8150	745	17280
Mar 20	826.2, 832.6, 821.2, 832	22140	2449	52865
Apr 20	815, 823.6, 811.6, 823.2	2965	278	8140
May 20	812.8, 819, 812.6, 819	45	8	115
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	3924, 3970, 3872, 3964	15785	1416	21185
Mar 20	3900, 3940, 3858, 3930	48845	5801	143650
Apr 20	3922, 3932, 3860, 3920	19950	2160	99925
May 20	3912, 3938, 3886, 3930	3675	506	19525
Jun 19	3918, 3918, 3918, 3918	15	3	370
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	6658, 6866, 6628, 6832	2515	375	2785
Mar 20	6800, 6948, 6681, 6904	15660	2468	55570
Apr 20	6860, 7024, 6770, 6985	1900	317	4705
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	3916, 4040, 3900, 4017	28480	2105	20170
Apr 20	3906, 4020, 3895, 4003	11310	923	18270
May 20	3942, 4059, 3932, 4042	970	91	4600
Jun 19	4050, 4094, 4050, 4073	80	8	1100
Jul 20	4100, 4182, 4080, 4080	30	3	10
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Mar 13	3550.1, 3561, 3507.5, 3517.1	2.2	22	7.1
Apr 15	3482.5, 3500.1, 3481.4, 3486	0.9	7	1.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6100, 6277, 6088, 6263	3380	287	7380
May 20	6165, 6275, 6165, 6275	100	10	850
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	13590, 13765, 13510, 13680	798	243	2157
Apr 20	13425, 13640, 13400, 13615	567	161	1836
May 20	13525, 13650, 13520, 13640	72	11	84
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	5860, 5940, 5856, 5882	635	116	4500
Apr 20	5846, 5900, 5828, 5862	210	40	4690
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	138.2, 138.6, 137.8, 138.5	3915	2755	5364
Mar 31	138.7, 139.05, 138.35, 139	156	120	636
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	434.75, 435.55, 433.25, 435.25	17627.5	5875	12707.5
Mar 31	436, 437.95, 435.4, 437.65	572.5	211	1400
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	145.95, 146.5, 145.3, 146.1	7226	4908	5702
Mar 31	146.8, 147.25, 146.25, 146.9	361	356	934
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	953, 953.7, 942.4, 948.1	13134	7656	3762
Mar 31	951.2, 952.5, 944, 949.9	198	124	373.5
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	168.75, 168.75, 167.6, 168.1	21933	12159	22312
Mar 31	170, 170.1, 168.85, 169.55	1714	1002	5850
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40431, 40470, 40306, 40408	5.46	4633	16.77
Jun 05	40570, 40610, 40465, 40580	0.21	147	6.01
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32236, 32330, 32236, 32286	0	174	0.01
Mar 31	32227, 32300, 32225, 32273	0	45	0
Apr 30	32307, 32307, 32307, 32307	0	1	0
May 29	32989, 32989, 32989, 32989	0	1	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40352, 40398, 40251, 40356	0.62	5305	0.86
Apr 03	40404, 40444, 40290, 40401	0.1	882	0.31
May 05	40461, 40500, 40385, 40438	0	10	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4004, 4007, 3991, 4000	0	611	0.01
Mar 31	4009, 4017, 4009, 4012	0	190	0
Apr 30	3949, 4001, 3949, 3954	0	2	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	45693, 45699, 45406, 45622	267.39	7286	295.62
May 05	46268, 46268, 45946, 46199	6.51	184	31.95
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	45660, 45850, 45442, 45642	27.79	19790	32.84
Apr 30	46315, 46315, 46000, 46190	4.24	2981	7.89
Jun 30	46845, 46845, 46520, 46567	0.02	18	0.18
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	45808, 45808, 45439, 45640	80.67	13001	56.62
Apr 30	46270, 46286, 46000, 46195	5.72	948	9.44
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	127.9, 131.6, 127.9, 131.2	70955mb	31439	51921mb
Mar 26	131.5, 134.2, 130.9, 133.9	3861mb	2278	6506mb
Apr 27	136.2, 139, 135.8, 138.8	455mb	223	804mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3580, 3632, 3580, 3625	12920bl	73918	3748bl
Mar 19	3641, 3659, 3632, 3654	378bl	2969	445bl
Apr 20	3670, 3686, 3665, 3674	1bl	7	6bl
सायं सत्र (मंगलवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Feb 28	19000, 19180, 19000, 19160	2372	380	27181
Mar 31	19290, 19450, 19290, 19440	893	141	8622
Apr 30	19620, 19640, 19620, 19630	13	3	1454
May 29	19880, 19880, 19880, 19880	09	2	13
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1055, 1059, 1054, 1058	764	112	1068
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1055, 1059, 1052.5, 1058.5	748	428	3601
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Feb 28	740.5, 743, 723.5, 733	28140	1886	44420
Mar 31	737, 739.9, 718.5, 726.3	18700	1201	23900
Apr 30	736.2, 739.3, 714, 721.9	3910	300	8030
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	846.6, 849, 837, 848.4	8130	818	20245
Mar 20	832.8, 833.8, 823, 829.6	14080	1708	54085
Apr 20	825.8, 826.6, 814.6, 820.2	2545	338	6790
May 20	815, 817, 815, 816.4	15	3	110
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Feb 28	136.8, 138.6, 136.45, 138.3	13505	8996	4741
Mar 31	137.95, 139.2, 137.4, 138.9	613	498	596
Copper MCX(1 K)				
Feb 28	431.2, 434.9, 431.2, 433.75	39577.5	13114	10555
Mar 31	433.3, 436.55, 433.3, 435.5	747.5	286	1247.5
Lead MCX(1 K)				
May 29	147.2, 148, 147.2, 147.6	2	2	7
Lead Mini MCX(1 K)				
Feb 28	143.05, 146.3, 142.95, 145.95	20910	12822	5034
Mar 31	144.45, 147, 143.9, 146.75	621	551	824
Apr 30	146.8, 146.9, 146.8, 146.85	2	2	2
Nickel MCX(1 K)				
Feb 28	949.5, 960.3, 949.5, 952.1	20487	12169	1839
Mar 31	958.4, 959, 951, 952.4	336	201	327
Zinc MCX(1 K)				
May 29	171.3, 171.9, 171.3, 171.65	4	4	16
Zinc Mini MCX(1 K)				
Feb 28	168.2, 169, 166.8, 168.3	65157	37283	17867
Mar 31	169.7, 170.2, 168.1, 169.75	3136	2154	4980
Apr 30	170.5, 170.7, 169.95, 170.35	5	5	14
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Apr 03	40566, 40577, 40300, 40410	11.52	9684	16.21
Jun 05	40616, 40720, 40472, 40578	0.33	303	5.84
Gold Guinea MCX(8 G)				
Feb 28	32275, 32300, 32133, 32262	0.01	507	0.01
Mar 31	32261, 32285, 32126, 32192	0	79	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Mar 05	40510, 40510, 40243, 40353	1.78	14533	0.75
Apr 03	40560, 40560, 40285, 40398	0.3	2463	0.3
May 05	40530, 40612, 40405, 40451	0.01	47	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Feb 28	4013, 4013, 3985, 4003	0.01	2198	0.01
Mar 31	4026, 4026, 4009, 4014	0	668	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	46073, 46170, 45610, 45664	579	15985	265.77
May 05	46540, 46682, 46162, 46210	8.46	257	29.46
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	46100, 46177, 45640, 45687	65.35	47044	28
Apr 30	46700, 46710, 46201, 46252	6.48	4769	7.09
Jun 30	47100, 47100, 46670, 46847	0.01	12	0.17
Aug 31	47997, 47997, 47997, 47997	0	1	0.02
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	46160, 46190, 45625, 45677	190.84	30189	45.3
Apr 30	46700, 46700, 46209, 46250	6.42	1184	8.06
तेल एवं गैस				
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Feb 25	126.9, 127.8, 125.6, 127.1	167410mb	70625	48439mb
Mar 26	130.1, 130.8, 128.9, 130	5785mb	3499	6685mb
Apr 27	135.4, 135.8, 134.2, 135	420mb	262	626mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Feb 19	3555, 3614, 3555, 3580	43331bl	241873	2650bl
Mar 19	3598, 3640, 3593, 3608	1280bl	10206	456bl
Apr 20	3636, 3663, 3617, 3627	6bl	43	6bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

ट्रंप के स्वागत में तैयार स्टेडियम

दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है

विनय उमरजी

बैठने की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर चर्चित सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम (मोटेरा स्टेडियम) को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सजाया संवारा जा रहा है।

मोटेरा स्टेडियम में अधिकतम 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यहां 2019 में टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी की तर्ज पर ट्रंप और मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

प्रमुख वास्तुशिल्प कंपनी पॉपुलस, परियोजना प्रबंधन परामर्श कंपनी स्तूप कंसल्टेंट्स और डेवलपर एलऐंडटी को गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) ने स्टेडियम के पुनर्विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। इन तीनों कंपनियों की जोड़ी 24 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पूरे जोर शोर से काम में जुटी है। तकरीबन 800 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से तैयार किया गया यह स्टेडियम दुनिया भर में अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट मैदान (एमसीजी) की याद दिलाएगा जिसमें 1,000,24 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जीसीए के नियंत्रण वाले मोटेरा स्टेडियम में एक मुख्य क्रिकेट मैदान के साथ ही दो उससे छोटे मैदान, चार लॉकर कक्ष, 75 वातानुकूलित कॉर्पोरेट बॉक्स और जीसीए के सदस्यों के लिए एक कल्ब हाउस होंगे।

इस स्टेडियम में अब तक एक ही प्रवेश द्वार था जिसकी जगह अब इसमें तीन प्रवेश द्वार होंगे। साथ ही क्लबहाउस में इनडोर और आउटडोर स्पॉर्ट्स के साथ 55 कक्ष होंगे। इसके अलावा यहां कई सारे रेस्तरां, ओलंपिक के आकार वाले स्विमिंग पूल, जिम और पार्टी स्थल के साथ ही कई और सुविधाएं होंगी। इस विशाल स्टेडियम में एक क्रिकेट एकेडमी और इनडोर अभ्यास पिच भी होगी। भविष्य में इसके एक प्रमुख द्वार को मेट्रो रेल स्टेशन से जोड़ा जाएगा जो फिलहाल निर्माणाधीन है।

25 वर्ष पुराने मोटेरा स्टेडियम को पूरी तरह से ध्वस्त कर उसकी जगह नया स्टेडियम खड़ा करने और इसे स्वदेशी सुविधाओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का विचार प्रधानमंत्री मोदी ने जीसीए के तत्कालीन अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिया था।

इसके बाद जीसीए के अध्यक्ष पद पर मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर अमित शाह ने पदभार ग्रहण किया और इस विशाल परियोजना का चार्ज अपने हाथों में लिया। इस काम में उन्हें जीसीए के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष परिमल नाथवानी और पूर्व संयुक्त सचिव जय शाह का भरपूर साथ मिला। फिलहाल, जीसीए के उपाध्यक्ष के तौर पर धनराज नाथवानी जीसीए टीम सदस्यों के साथ नए मोटेरा स्टेडियम के निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे हैं।

24 फरवरी को होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) स्टेडियम को भरने के लिए 1,10,000 भागीदारों को लाने पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हवाईअड्डे से स्टेडियम के रास्ते पर स्वागत के लिए लोगों को लाने की भी तैयारी की जा रही है।

राज्य सरकार के मुताबिक अधिकारियों, छात्रों, कार्यरत पेशेवरों और कारोबारियों से समान रूप से ट्रंप-मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा कई अनिवासी गुजराती (एनआरजी) भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को ह्यूस्टन में आयोजित किए गए हाउडी मोदी की तर्ज पर केम छो ट्रंप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि, इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कार्यक्रम से पहले अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र के करीब 16 सड़क खंडों का मरम्मत या चौड़ीकरण किया जा रहा है। स्टेडियम के सामने सड़क डिवाइडरों पर पौधरोपण किया जा रहा है।

राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप और मोदी साबरमती आश्रम में करीब आधा घंटा ठहर सकते हैं जिसके बाद मोटेरा स्टेडियम में दो घंटे का सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अहमदाबाद यात्रा की तरह ही ट्रंप की यात्रा के दौरान भी हवाईअड्डे से आश्रम और स्टेडियम दोनों रास्तों के प्रमुख जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा।

इस बीच, एएमसी भागीदारों के लिए पार्किंग स्थलों का इंतजाम करने के साथ ही 24 फरवरी को ट्रैफिक को पुनर्निर्देशित करने पर भी काम कर रहा है। अनुमानित भागीदारों की पृष्ठभूमि का निरीक्षण कर राज्य सरकार सुरक्षा उपायों पर भी काम कर रही है।

मोटेरा स्टेडियम में अधिकतम 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं

भारत आने को उत्सुक ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस महीने अपनी भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं और उन्होंने संकेत दिए कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गुजरात के अहमदाबाद भी जाएंगे और वहां एक स्ट्रेडियम में मोदी के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों देश कुछ मसलों के समाधान और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने को लेकर व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइटहाइजर के बीच फोन पर कई दौर की बातचीत हुई है।

वास्तविक चुनौतियों का हल करने वालों को सम्मान

बीएस संवाददाता

बिज़नेस स्टैंडर्ड बेस्ट बी-स्कूल प्रोजेक्ट अवॉर्ड 2019 में वैसे लोग विजेता बन कर उभरे हैं जो कॉरपोरेट जगत में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने का मॉडल तैयार कर रहे हैं। मसलन इनमें स्थानीय स्तर की सक्षम डिलिवरी, मॉल में परफ्यूम की बिक्री की तकनीक, माइक्रोफाइनैंस में डेटा एनालिटिक्स और वाहन निर्माण क्षेत्र में सुधार से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुंबई के कपिल गवली को शीर्ष पुरस्कार मिला जिन्होंने सामानों की कम समय में डिलिवरी की एक बेहतरीन परियोजना पर काम किया जिसमें सामान का चयन करने, उसे भेजने के लिए मार्ग का निर्धारण करने, स्थानीय भंडारगृह के लिए भंडार नीति बनाना शामिल है। गवली ने फ्लिपकार्ट के लिए भी एक मॉडल तैयार किया जिसके जरिये ग्राहकों को समय पर सामान की डिलिवरी कराई जा सके, भंडारगृह में सामान को ढूंढने और लेने में वक्त कम लगे। गवली का कहना है कि स्थानीय डिलिवरी मॉडल में समय अहम है और मेरी परियोजना में इसी चुनौती को दूर करने की कोशिश की गई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जी तेजा इस अवॉर्ड के पहले रनर-अप रहे जिन्हें मॉल में टाइटन स्किन परफ्यूम की बिक्री और मार्केटिंग तकनीक के लिए सम्मानित किया गया। दूसरे रनर-अप का खिताब जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐंड एंटरप्रेन्योरशिप, चेन्नई के विवेक सत्यमूर्ति और सिंबायोसिस सेंटर ऑफ मैनेजमेंट ऐंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के आयुष त्रिवेदी को मिला। सत्यमूर्ति ने बीएमडब्ल्यू के संयंत्र में कलपुर्जों के परिवहन के लिए सक्षम मॉडल तैयार किया था जो उनके मार्ग ट्रेन परियोजना का हिस्सा है और इसमें कार्यबल के बेहतर आवंटन के साथ ही माल की उपलब्धता में सुधार और उत्पादन में बढ़ोतरी पर ध्यान दिया गया। दूसरी तरफ त्रिवेदी को नकदी जोखिम मूल्यांकन और कर्ज डिफॉल्ट अनुमान मॉडल से जुड़ी परियोजना के लिए सम्मान मिला जिसे उन्होंने समुन्नति फाइनैंशियल इंटरमेडिएशन के लिए तैयार किया था जो कृषि से जुड़े वैल्यू चेन के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय समाधान देती है। बी2बी ई-कॉमर्स उड़ान के सह संस्थापक सुजीत कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सफलता का मंत्र ज्ञान की भूख और खुद से ज्यादा सक्षम लोगों को नौकरियां देना और उनकी तरक्की के लिए गुंजाइश बनाना है। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने देश के बेहतरीन बिजनेस स्कूलों के छात्रों को सम्मानित करने के लिए 2007 में इस अवॉर्ड की शुरुआत की। इसके 13वें संस्करण में 174 प्रवृष्टियां मिलीं जिनमें से प्रमुख 15 और आखिर में पांच को चुना गया।

बुधवार को मुंबई में बिज़नेस स्टैंडर्ड बेस्ट बी-स्कूल प्रोजेक्ट अवॉर्ड 2019 के लिए जुटे निर्णायक मंडल के सदस्य सीजी पावर के वैश्विक प्रमुख (आंतरिक ऑडिट) सुनील पंजवानी, मैकिंजी के सीनियर पार्टनर रजत गुप्ता, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की सीएमडी निशी वासुदेव, ऐक्सिस बैंक के प्रमुख (मानव संसाधन) राजकमल वेंपति, रीडिफ डॉट कॉम के संस्थापक और अध्यक्ष अजित बालकृष्णन (निर्णायक मंडल के अध्यक्ष), ब्रांड बिल्डिंग डॉट कॉम के संस्थापक अंबी परमेश्वरन और बीएसई के एमडी और सीईओ आशिष चौहान (बाएं से दाएं) फोटोः कमलेश पेडणेकर

'महाराजा' की यादगार चीजों की प्रदर्शनी

एयर इंडिया के विनिवेश के बावजूद कंपनी की कलाकृतियों और यादगार चीजों को सहेजने की हो रही है कोशिश

पवन लाल

कई सालों तक कर्ज और आर्थिक संकट से जूझती रहने वाली देश की सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया का विनिवेश करने की सरकार की घोषणा के बाद कंपनी के कला संग्रह की प्रदर्शनी की शुरुआत गुरुवार को मुंबई के नेहरू केंद्र में होगी।

आयोजकों का कहा है कि महाराजा ऑफ स्काई - एन इंडियन हैरिटेज (आकाश के महाराज - एक भारतीय विरासत) नामक इस प्रदर्शनी का आयोजन सोसाइटी फॉर कल्चर ऐंड एनवायरनमेंट द्वारा किया जा रहा है। इसमें सौ से ज्यादा यादगार चीजें शामिल हैं जिनमें से ज्यादातर प्रतिकृतियां हैं, लेकिन एयर इंडिया से उधार ली हुई कुछ मौलिक वस्तुएं भी शामिल हैं। इन मौलिक वस्तुओं में जेआरडी टाटा की उड़ान रिकॉर्ड वाली बुक, एयरलाइन के लोगो वाली रॉयल डॉल्टन की चीनी मिट्टी की प्लेट, फ्लाइट रिकॉर्डर और हवाई जहाज के छोटे मॉडल भी शामिल हैं, जबकि प्रतिकृतियों में पोस्टर और कैलेंडरों की तस्वीरें, डायरियां, डायरी, कोस्टर, पोस्टर और पेंटिंग शामिल हैं।

एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि पहले संपूर्ण कला संग्रह और संग्रह की वस्तुओं को केवल इसी के लिए तैयार किए गए नए संग्रहालय में रखने की योजना थी जिसे रद्द कर दिया गया है। अब निकट भविष्य में पूरा कला संग्रह निकट दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्राहलय में रखा जाएगा। दूसरे शब्दों में विनिवेश हो या न हो, लेकिन कला और यादगार चीजों की बिक्री नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी एयर इंडिया के शानदार अतीत और संस्कृति का गवाह होगी जिसका अपना अलग आकर्षण और शैली हुआ करती थी। वह कहते हैं कि सारी मुश्किलों के बावजूद यह विमानन कंपनी अब भी 40 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान भरती है और रोजाना इसकी 450 उड़ानें संचालित होती हैं।

एयर इंडिया में कंपनी को बढ़ावा देने के लिए विभागीय बजट के जरिये कला में निवेश करने की रवायत जारी थी। एयर इंडिया के कला विभाग की कमान पहले युवा प्रतिभाओं ने संभाली जो बाद में स्थापित कलाकार बने जिनमें बी. प्रभा भी शामिल हैं जिनकी पेंटिंग को पहले एयर इंडिया ने ही खरीदा।

एयर इंडिया के मूल संग्रह में छह फीट की एम एफ हुसैन की पेंटिंग शामिल है। इसके अलावा वी एस गायतोंडे, अंजलि इला मेनन, जितीश कलात और शक्ति बर्मन जैसे कलाकारों की कलाकृतियां भी शामिल हैं। कपड़े, प्रतिमा, लकड़ी की कलाकृतियां और एश-ट्रे भी तैयार किए गए। इसके अलावा इन संग्रहों में डायरी, पोस्टर और गोवा के कलाकार मारियो मिरांडा के स्केच भी शामिल हैं।

अब सवाल यह है कि कंपनी के संग्रह में कितनी कलाकृतियां शामिल हैं ? एक अनुमान के मुताबिक अनुमानत: 10,000 से 40,000 कलाकृतियां हैं हालांकि यह जानकारी नहीं है कि संग्रह के कैटलॉग में कितनी शामिल की गई हैं। एयर इंडिया के अधिकारी ने संख्या बताने से इनकार करते हुए यह कहा कि लेटर हेड, सालाना डायरी और कोस्टर्स को भी संग्रह में शामिल किया गया है ऐसे में तादाद ज्यादा होगी।

क्या इस पूरे संग्रह का कोई मूल्यांकन किया गया है ? इस सवाल पर विशेषज्ञों का कहना है कि पोर्टफोलियो में कलाकृतियों की विविधता के कारण इसे किसी एक संख्या में सीमित करना मुश्किल है। पिरामल आर्ट फाउंडेशन के निदेशक अश्विन राजगोपालन कहते हैं कि एयर इंडिया के मौलिक पोस्टर ही 50,000 से 60,000 रुपये के बीच बिकते हैं जो सिर्फ एक पोस्टर के लिए काफी अधिक दाम हैं।

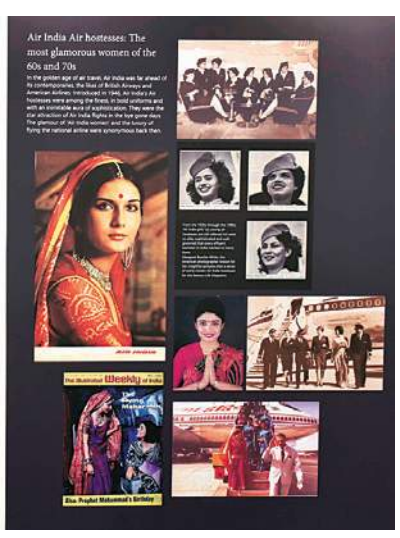

आईआईएम-कलकत्ता में छात्रों को शानदार वेतन की पेशकश

अभिषेक रक्षित

इस साल भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता (आईआईएम-सी) में कंपनियों ने छात्रों की प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान अब तक के सबसे ज्यादा औसत वेतन की पेशकश की है। संस्थान के 2020 के एमबीए बैच के शीर्ष 10 फीसदी और कक्षा के शीर्ष एक-चौथाई छात्रों के लिए क्रमश: 54.5 लाख रुपये और 41.8 लाख रुपये के पैकेज की पेशकश की है। यहां औसत वेतन रिकॉर्ड स्तर पर 28 लाख रुपये है जबकि मध्यम स्तर का वेतन भी 25.5 लाख रुपये है। आईआईएम-कलकत्ता में प्लेसमेंट की प्रक्रिया में 136 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 439 छात्रों को 492 ऑफर मिले। इस पेशकश में छात्रों को ड्रीम, वेट और होल्ड जैसे विकल्प भी दिए गए। नियोक्ता छात्रों के एक बड़े पूल से भी चयन कर सकते थे और अपनी पसंद के मुताबिक सबसे ज्यादा उपयुक्त उम्मीदवार को नौकरी की पेशकश कर सकते थे।

आईआईएम-सी में करियर डेवलपमेंट ऐंड प्लेसमेंट ऑफिस के चेयरपर्सन अभिषेक गोयल ने बताया, 'सुपरसेट लागू करने से हमारी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सक्षम हो गई है।' सुपरसेट एक ऐसा मंच है जो कॉलेजों के लिए कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया स्वचालित करने में मददगार साबित होता है और इसके जरिये नियोक्ताओं को देश के विभिन्न कॉलेजों के प्रतिभाशाली छात्रों को नौकरियों की पेशकश करने में आसानी होती है। अक्टूबर 2019 में हुए समर प्लेसमेंट का ही रुझान जारी रहा। कंसल्टिंग क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता साबित हुआ और इस क्षेत्र से छात्रों को करीब 31 फीसदी नौकरियों के ऑफर मिले। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकिंजे ऐंड कंपनी, बेन ऐंड कंपनी, कियर्ने, प्राइसवॉटरहाउसकूपर्स और एक्सेंचर इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां थीं जिन्होंने छात्रों को ऑफर दिए। वित्तीय क्षेत्र और प्राइवेट इक्विटी-वेंचर कैपिटल (पीई-वीसी) कंपनियों ने 83 नौकरियों की पेशकश की जिसमें से कुल 17 फीसदी को ही स्वीकार किया गया। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, आर्गा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, गाजा कैपिटल, जेपी मॉर्गन चेस और अन्य कंपनियों ने आईआईएम-सी के 55वें बैच के लिए पेशकश की।

नौकरियों की कुल पेशकश में प्रबंधन, बिक्री एवं मार्केटिंग की हिस्सेदारी 30 फीसदी तक थी। इस क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों में टीएएस, आदित्य बिड़ला ग्रुप, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, रिलायंस, वेदांत, ट्रूनॉर्थ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट-पामोलिव, आईटीसी, मॉन्डेलेज और फिटजी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं। नौकरियों की पेशकश में प्रोडक्ट मैनेजमेंट, आईटी/एनालिटिक्स की हिस्सेदारी 22 फीसदी तक रही और इसके प्रमुख नियोक्ताओं में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सेल्सफोर्स, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उड़ान, ईएक्सएल सर्विस, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचसीएल, यूनाइटेडहेल्थ ग्रुप (ऑप्टम) और मास्टरकार्ड शामिल है।